



दैनिक नव प्रदेश

प्रदेश के साथ पूरा देश...

सरकारी खर्च पर बढ़ेगा रोजगार : एक करोड़ युवाओं को भत्ता, पहली नौकरी पाने वालों को तोहफा

युवा को रोजगार, मध्य वर्ग को राहत

किसानों, महिलाओं, वितनभोगियों को भी राहत



यूं बदलेगी देश की दशा

- युवाओं व बेरोजगारों पर सरकार की नजर**
- 4.1 करोड़ युवाओं के लिए पांच साल में रोजगार
 - ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपये तक के एक महीने का वेतन
 - कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना
 - सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3000 हजार रुपये प्रत्येक महीना
 - 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास की योजना
 - 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन
 - पांच साल में एक करोड़ युवाओं को पांच सौ टॉप कंपनियों में इंटरशिप
 - 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना
 - सरकार की योजनाओं और नीतियों के तहत किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले युवाओं को धरोलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण

- खेती-बाड़ी पर विशेष जोर**
- कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रु का आवंटन
 - किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी
 - प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा
 - प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे
 - तीन साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने हेतु कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना को लागू किया जाएगा।

- उद्योग व बिजली के लिए खुला पिटाटा**
- अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास
 - 21,400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं
 - आंध्र प्रदेश को मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता

- महिलाओं को फायदा**
- महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल तीन लाख करोड़ रुपये का आवंटन

- जनजातीय बहुल गांव में सरकार**
- जनजातीय-बहुल गांवों व आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के विकास के 63,000 गांवों के पांच करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे।

- बैंकिंग सुविधाएं**
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खुलेंगी
 - गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी
 - तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये
 - खरीददारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़
 - इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपये के व्याज रहित दीर्घावधि ऋण

- खनिज व खनन**
- पहले से किये गये खोज के आधार पर खनन के लिए अपतटीय ब्लॉकों के पहले भाग की नीलामी शुरू होगी
 - 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट

नौकरीपेशा लोगों को राहत की बूंदें : आयकर टैक्स स्लैब में थोड़ा सा बदलाव

निर्मला गणित : 64000 रु महीने तक की कमाई कर के दायरे में नहीं

17,500 रुपए तक की होगी बचत



नए टैक्स स्लैब	
0 से 3 लाख रुपये	0%
3 से 6 लाख रुपये	5%
6 से 9 लाख रुपये	10%
9 से 12 लाख रुपये	15%
12 से 15 लाख रुपये	20%
15 लाख से ऊपर	30%

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकरदाताओं को राहत देते हुए नई कर प्रणाली के टैक्स स्लैब में बदलाव का एलान किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि नई दरों के अमल में आने से देश के करीब चार करोड़ करदातों को आयकर के मद में 17500 रुपये तक का लाभ होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन मद में मिलने वाली 50 हजार रुपये की छूट की राशि को बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया है। नई कर प्रणाली के तहत तीन लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री रखा गया है। हालांकि, सात लाख रुपये तक

की आमदनी वालों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसका कारण हम आपको आगे बताएंगे। पहले जानिए इस बार टैक्स दरों में क्या बदलाव किया गया? वित्त मंत्री के बजट में किए गए एलानों के बाद अगर किसी करदाता की सालाना आय 7 लाख 75 हजार रुपये तक है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये घटाने के बाद उसकी

पहले की स्थिति में कर की गणना	
कुल आय-स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 घटाने पर	8,50,000
तीन लाख तक कर 0%	8,50,000-50000= 7,50,000
3-6 लाख पर 5%	15000
बचे दो लाख पर कर 10%	20000
कुल कर देयता	35000

नई दरों के बाद कर की गणना	
कुल आय-स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 घटाने पर	8,50,000
तीन लाख तक कर 0%	8,00,000-75,000= 7,75,000
3-7 लाख पर 5%	20,000
बचे 75000 10%	7,500
कुल कर देयता	27,500
करदाता को लाभ : 35,000-27,500 = 7,500 रुपये	

आमदनी 7 लाख रुपये सालाना हो जाएगी। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64000 या 64500 रुपये के आसपास है तो उसे

नई कर प्रणाली में कोई आयकर चुकाने की जरूरत नहीं है। बजट से पहले की स्थिति में सालाना आमदनी 7,50,000 रुपये तक रहने पर ही करदाता को टैक्स देने से राहत मिलती थी।

एक करोड़ लोगों को मिलेगा घर

हाउसिंग सेक्टर को एक साल में 15 फीसदी वृद्धि का अनुमान

23 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केन्द्रीय बजट पेश किया। इसमें एक करोड़ गरीब व मध्यम वर्ग परिवारों को घर मुहैया करवाने के लिए सरकार ने ब्याज पर सब्सिडी योजना का एलान किया है। महिलाओं को विशेषरूप से प्राँपट्री खरीदने पर राज्य सरकारों से स्टैप्ड ड्यूटी पर छूट देने को कहा गया है, जिसमें महिलाएं अपने घर का सपना पूरा कर सकें। बजट भाषण में बोलते हुए वित्तमंत्री ने एलान किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण किया



जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक श्रमिक जो कि रोजगार के लिए शहरों में आते हैं उनके लिए सरकार छात्रावास शैली के आवासों के साथ किराये के आवास भी बनाएगी। यह सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल (पीपीपी) पर आधारित होगा। हिरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन एवं एमी नीरजन हीरानंदानी का कहना है कि

बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाए जाने से हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ अगले एक साल 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ेगी। सरकार ने अप्रोडेबल हाउसिंग के लिए जो एलान किया है, उससे होम फाइनेंस कंपनियों की कारोबारी वृद्धि में 25 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि अगले पांच सालों में जब हम पांच

ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे तो भारत के जीडीपी में हाउसिंग और इन्फ्रा का योगदान 20 प्रतिशत होगा। मौजूदा समय में यह जीडीपी में 7 प्रतिशत की योगदान है।

हाउसिंग फाइनेंस और सीमेंट कंपनियों को मिलेगा लाभ

स्मॉल केस मैनेजर और संस्थापक सोनम श्रीवास्तव का कहना है कि तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की सरकार की घोषणा से रियल एस्टेट मार्केट में तेजी तो आएगी लेकिन इसका सीधा फायदा हाउसिंग फाइनेंस और सीमेंट कंपनियों को होगा। हाउसिंग फाइनेंस फर्मों को लोन की मांग बढ़ने से लाभ होगा जिससे नए बाजार और अवसर भी पैदा होंगे। हालांकि उन्हें क्रेडिट मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

इनको भी साधा

- बिहार को तोहफा**
- विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा और राजगीर का व्यापक विकास।
 - बिहार में कोसी-मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

- ओडिशा को विशेष मदद**
- ओडिशा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभयारण्य, प्राकृतिक भू-दृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास के लिए सहायता

- इन राज्यों को आर्थिक सहायता**
- आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की विशेष वित्तीय सहायता मिलेगी। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।

- इन राज्यों को आर्थिक सहायता**
- सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता देगी

सस्ता-महंगा

जुता-चप्पल, सोना-चांदी, अन्य कीमती धातु, कपड़ा, कैसर औषधियां, एक्सरे उपकरण, मोबाइल फोन, चार्जर, मोबाइल फोन कल पुर्जें, सौर ऊर्जा के उपकरण, मछली, मछली चारा, प्राकृतिक ग्रेफाइट, प्राकृतिक रेत, धातु, दुर्लभ धातु, निकल, पोटेशियम, लिथियम, टिन, युद्धपोत उपकरण और कलपुर्जें, पशुओं की खाल सस्ते होंगे, जबकि महंगी होने वाली वस्तुओं में प्लास्टिक, पीवीसी-प्लेक्स सीट, बड़े छते, प्रयोगशाला रसायन, भुना सुखे मेवा, सौर ऊर्जा ग्लास और टिन शामिल हैं।

शेयर और म्यूचुअल फंड से कर रहे हैं तगड़ी कमाई अब सरकार को भी दीजिए टैक्स

शेयर बाजार में इस समय बहार ही बहार है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 80,000 से ऊपर है। शहरों में तो इस समय हर तीसरा व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश कर रहा है। एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि देश की करीब 20 फीसदी आबादी शेयर बाजार में सीधे या शेयर बाजार से जुड़े प्रॉडक्ट में निवेश कर रहे हैं। इन सबकी अच्छी आमदनी हो रही है। शायद यही कारण है कि सरकार ने इस बजट में शेयर बाजार से होने वाली आमदनी पर टैक्स का रेट



आमदनी को शार्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। लेकिन यदि वही अपने निवेश को एक साल तक बनाये रखता है तो वह लॉन्ग टर्म माना जाता है। इसलिए उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को शार्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट में बदलाव करके पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था में कुछ हद तक बदलाव किया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पहले 10% की दर से टैक्स लगता था। अब इसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इसी तरह शार्ट टर्म कैपिटल गेन पर अभी तक 15 फीसदी की दर से टैक्स लगता था। अब इसे बढ़ा कर 20 फीसदी कर दिया गया है।

इनकम टैक्स को आसान बनाएगी मोदी सरकार

तीन रोजगार योजना शुरू करेगी सरकार

30 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद



नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि वो रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि ये ईपीएफओ में एनरोलमेंट पर ब्रेस्ट होंगी। पहली योजना के तहत सभी सेक्टर में वर्कफोर्स में एंट्री करने वालों को एक महीने की सैलरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दूसरी योजना में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़े मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में और ज्यादा नौकरियों को बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री ने कहा, रोजगार के पहले चार सालों में ईपीएफओ

कंट्रीब्यूशन के संबंध में कर्मचारी और एंप्लॉयर को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर इंसेंटिव दिया जाएगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं और उनके एंप्लॉयर को लाभ मिलने की उम्मीद है। सीतारमण ने कहा कि तीसरी योजना के तहत सभी सेक्टर में और अतिरिक्त रोजगार को लिया जाएगा उन्होंने कहा, एक लाख रुपए तक मासिक सैलरी के अंतर्गत सभी अतिरिक्त रोजगार को गिना जाएगा। सीतारमण ने कहा कि सरकार हर एक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के रूप में एंप्लॉयर को दो सालों तक 3,000 रुपए प्रतिमाह तक की राशि रीडबर्स करेगी।

महिलाओं के घर खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में कटौती पर विचार



नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार महिलाओं के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने और इसे शहरी विकास योजनाओं का हिस्सा बनाने पर विचार करेगी। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं की ओर से खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी के लिए ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित

करेगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करेगी, जो ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी वसूलना जारी रखते हैं, ताकि वे सभी के लिए रेंट को कम कर सकें और महिलाओं की ओर से खरीदी गई संपत्तियों के लिए ड्यूटी को और कम करने पर भी विचार कर सकें। इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया जाएगा।

कैपिटल गेंस टैक्स से छूट की लिमिट बढ़ाई

बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कैपिटल गेंस टैक्स से छूट की सीमा बढ़ाने का भी ऐलान किया है। लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि कैपिटल गेंस टैक्स से छूट की सीमा 1% से बढ़ाकर 1.25 फीसदी किया गया।

राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत तक रहने की संभावना

नई दिल्ली। सरकार की वित्तीय स्थिति को और मजबूत बनाने की राह पर आगे और प्रगति का विश्वास जताते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा चालू वित्त वर्ष में सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से बाजार से सकल 14.01 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटायेगी। वर्ष के दौरान जुटया गया कर्ज शुद्ध रूप में 11.63 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि 2021 में उन्होंने राजकोष को



मजबूत बनाने की जो वृहद योजना प्रस्तुत की, उससे अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी सेवा हुई है, और

सरकार अगले वर्ष घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रखेगी।

चालू वित्त वर्ष में 16.13 लाख करोड़ घाटा रहने का अनुमान

चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 16.13 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बराबर) रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष, संशोधित अनुमानों में 16.54 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी के 5.6 प्रतिशत) के बराबर था। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले पांच साल तक अवसंरचना विकास को अपना ठोस समर्थन बनाये रखेगी। बजट में राज्यों को अवसंरचना विकास के लिये 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण का प्रावधान किया गया है। बजट में केंद्र सरकार को करों से शुद्ध प्राप्ति प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में ग्रामीण इलाकों में 25,000 छोट्टी बस्तियों तक सड़क पहुंचाने का लक्ष्य है।

बुनियादी, आर्थिक, सामाजिक पर फोकस

बुनियादी, आर्थिक, सामाजिक और अनुसंधान एवं विकास ढांचे को बढ़ाने की योजनाओं के साथ बजट में 11 लाख 11,111 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है जो जीडीपी के 3.4 प्रतिशत के बराबर है। पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार 2023-24 में पूंजीगत व्यय 9.49 लाख करोड़ रुपये था। पूंजीगत व्यय के लिये राजस्व खाते से दिये गये अनुदानों को जोड़ दें, तो वर्ष के दौरान प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.02 लाख करोड़ रुपये तक रहेगा।

टैक्स स्लैब में बदलाव

बजट में उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जाएगा। टैक्स स्लैब में बदलाव से करदाताओं को 17.5 हजार रुपये का फायदा होगा। बजट में परिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से चार करोड़ नौकरी पेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर दरों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा।

अनुमानित है। उन्होंने बजट में शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली। सीतारमण ने केंद्रीय बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार 500 शीप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति महीने इंटरशिप भत्ता और 6 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 5 साल में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास कर रही है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15 हजार रुपए तीन किश्तों में देगी। इनकम टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव के बाद टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। पहले सैलरी से होने वाली 15.75 लाख की इनकम पर 1 लाख 57 हजार 500 रुपए टैक्स बनता था। अब इन बदलाव के बाद 1 लाख 40 हजार रुपए टैक्स बनेगा।

टैक्सपेयर्स को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए बजट में इस रिजीम के टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव करने का एलान किया है। इतना ही नहीं, नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है लेकिन इसका फायदा उन्हीं टैक्सपेयर्स को मिलेगा जिन्होंने नए टैक्स रिजीम को अपनाया हुआ है। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ये बनेफिट नहीं मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये है। साथ ही बजट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के व्यापक रिव्यू का भी एलान किया गया है।

बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री से जब ये सवाल पूछा गया कि नए टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए लगातार एलान किए जा रहे हैं लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में कोई राहत नहीं दी गई है तो क्या ओल्ड टैक्स रिजीम को अप्रभावी बनाया जाएगा? इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, ओल्ड टैक्स रिजीम के सनसेट क्लॉज को लेकर अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूं। लेकिन सरकार का इरादा सरल टैक्स रिजीम बनाना है। उन्होंने कहा, ओल्ड टैक्स रिजीम को



सरल बनाने के लिए ही नए इनकम टैक्स रिजीम को लाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, इनकम टैक्स कानून के रिव्यू के जरिए सरल टैक्स रिजीम की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश है। लेकिन वित्त मंत्री ने साफ किया पुराने टैक्स रिजीम को अप्रभावी बनाने को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

70% ने चुना नया टैक्स रिजीम

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा, वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अभी आयकर रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। और अब तक 4 करोड़ जो आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है उसमें 70 फीसदी टैक्सपेयर्स ने नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर रिटर्न फाइल किया है।

2023 में नए टैक्स रिजीम को बनाया गया आकर्षक

साल 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण नए

इनकम टैक्स रिजीम को लेकर आई थीं। लेकिन इसमें बचत, बीमा, होमलोन के ब्याज पर टैक्स डिडक्शन का बनेफिट नहीं मिलता है। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ नहीं मिल रहा था। इसके चलते टैक्सपेयर्स ने इससे तौबा किया हुआ था। लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक फरवरी 2023 को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नए टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक के इनकम पर टैक्स छूट देना का एलान किया साथ नए टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का बनेफिट देने की घोषणा की। इसी के बाद टैक्सपेयर्स का नए टैक्स रिजीम की तरफ झुकाव बढ़ा है।

इनकम टैक्स कानून की होगी समीक्षा

बजट में वित्त मंत्री एलान किया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिव्यू किया जाएगा जिससे इसे सरल बनाया जा सके। साथ ही इसके जरिए विवादों को खत्म किया जा सके और कानूनी विवाद को राका जा सके। इससे कानूनी विवाद के चलते टैक्स डिमांडों को कम करने में भी मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगले छह महीने यानि 2025 में पेश होने वाले बजट से पहले रिव्यू को पूरा कर लिया जाएगा।

पुराने इनकम टैक्स रिजीम का टैक्स स्लैब

पुराने इकम टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब पर नजर डालें तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.50 लाख रुपये तक के इनकम पर टैक्स छूट है। 2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय पर 5 फीसदी, 5 - 10 लाख रुपये तक के इनकम पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक जिनकी आय है उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। 2.50 से 5 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी के दर से जो 12500 रुपये का जो टैक्स बनता है सरकार उसपर रिबेट देती है।

फिस्कल डेफिसिट पर ज्यादा फोकस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, 2024-25 में फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5% से नीचे पहुंचाना है।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करेगी सरकार

एजेंसी

नयी दिल्ली : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केन्द्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुये घोषणा की है कि सरकार 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' की शुरूआत करेगी। श्रीमती सीतारमण ने जोर देते हुये कहा कि इस अभियान को जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के



लिये शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और विशिष्ट

मानव संसाधन विकास के उद्देश्य 'संपूर्ण कवरेज' की अनुशंसा की गयी है। उन्होंने कहा कि यह योजना जनजातीय आबादी बाहुल्य गांवों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को संपूर्ण कवरेज प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 63 हजार गांव शामिल होंगे और इसका लक्ष्य देश के पांच करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित करना है।

करदाताओं को सौगात

युवाओं पर मेहरबान

7.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री छात्रों को 5 हजार रुपये प्रति माह इंटरनशिप भत्ता

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 का बजट लोकसभा में पेश किया। इस तरह से वित्त मंत्री ने लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। सीतारमण का एक घंटा 23 मिनट का बजट भाषण वेतनभोगी वर्ष के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। नई टैक्स रिजीम चुनने वाले करदाताओं के लिए अब 7.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। वित्त मंत्री ने बजट में रोजगार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की वृद्धि एक चमकता सितारा बना हुआ है, जो आने वाले वर्षों में ऐसा



ही बना रहेगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये

अनुमानित है। उन्होंने बजट में शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये



उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये होगा, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 फीसदी होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि हमारा लक्ष्य घाटे को 4.5 फीसदी से नीचे पहुंचाना है।

पहली बार रोजगार पाने वाले

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना में सभी औपचारिक क्षेत्रों में नये कामगार के रूप में शामिल होने वाले सभी नवनि्युक्त व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में प्रंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तीन किश्तों में किया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 रुपये होगा। इस योजना के अंतर्गत पात्रता सीमा एक लाख रुपये का मासिक वेतन होगा। उन्होंने कहा, इस योजना से 210 लाख युवाओं के लाभान्वित होने की आशा है।

दलहन, तिलहन और सब्जियों पर सरकार का जोर

शिक्षा क्षेत्र में 32 प्रतिशत की वृद्धि

शिक्षा पर 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार

नयी दिल्ली : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले बजट की तुलना 32 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार की योजनाओं और नीतियों के तहत जिस युवा को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उसकी मदद के लिए सरकार घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता देगी। इसके लिए ई-वाउचर हर साल एक लाख छात्रों की सीधे दिए जाएंगे, जिसमें लोन अमाउंट की तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी होगी। सीतारमण ने कहा कि कौशल विकास योजना के तहत एक करोड़ युवाओं को पांच साल में रोजगार के लिए कुशल बनाया जाएगा। वहीं, एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अपग्रेड किए जाएंगे और हर साल 25 हजार विद्यार्थियों को कौशल ऋण का दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार 500 शीप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरनशिप देगी। इंटरनशिप के दौरान पांच हजार रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं



के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में दखिले के लिए ऋण दिया जाएगा। ऋण का तीन प्रतिशत तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख विद्यार्थियों को मिलेंगे।

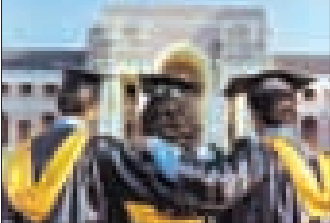
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि जारी वित्त वर्ष में कौशल भारत योजना के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि 2014 से 2024 तक सात नए भारतीय प्रद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और सात नए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईए) खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में तीन हजार नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) खोले गए हैं। वहीं 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी और 390 विश्वविद्यालय खुले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 28 प्रतिशत उपस्थिति पंजी बढ़ी है।

नौकरियों और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित पांच योजनाओं का एलान

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नौकरियों और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित पांच योजनाओं का एलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार पहली बार रोजगार के तहत एक लाख रुपये से कम वेतन होने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पहली बार पंजीकरण करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद देगी, जो तीन किस्तों में मिलेगी। ये किस्तें सीधे बैंक में स्थानांतरण (डीबीआई) के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कामकाजी महिला छात्रावास, शिशुगृह, महिला कौशल कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि सरकार घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए फाइनेंशियल हेल्प देगी। 2024-25 का आम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर दिए जाएंगे, जिसमें लोन अमाउंट का तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। कौशल विकास क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री की ओर से घोषित उपायों में 1,000 आईटीआई को 'हब और स्पोक मॉडल' में अपग्रेड करना, कोर्स को इंटरस्ट्री की स्किल जरूरत के हिसाब से बनाना और मॉडल स्किल लोन स्क्रीम में बदलाव करना शामिल है।



कृषि के लिए बनेगा 10 हजार बायो इनपुट सेंटर

एजेंसी

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ाया जाएगा और दो साल में एक करोड़ किसानों को इसमें शामिल कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था शार्पनिंग है और इसे निरंतर बनाए रखने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किये गये



हैं इसलिए कृषि तथा इससे संबंध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब, महिला और अन्नदाता को बजट में विशेष



नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी 3.0 के केन्द्रीय बजट 2024-25 को लोकसभा में पेश किया। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया।

सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी शानदार अपवाद बनी हुई है। ये आने वाले साल में भी ऐसी ही रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है, जो चार फीसदी के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। वित्तमंत्री ने कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केन्द्रीय परिव्यय के साथ 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ का प्रावधान

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केन्द्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्षों में अवसंरचना का निर्माण करने तथा इसे बेहतर बनाने के लिए किए गए पर्याप्त निवेश का अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम अन्य प्राथमिकताओं और राजकोषीय समेकन की आवश्यकताओं के अनुरूप, अगले 5 वर्षों में अवसंरचना के लिए सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष, मैंने पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह हमारी जीर्णोद्धार का 3.4 प्रतिशत होगा। इसी तरह बुनियादी ढांचे के लिए मदद प्रदान करने को लेकर राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कि हम राज्यों को उनकी विकास प्राथमिकताओं के अध्यधीन, अवसंरचना के लिए उसी पैमाने की सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ के दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है।



व्यवस्था की गई है ताकि शिक्षा के विकास तथा रोजगार के अवसरों को तेजी से बढ़ाया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा, खरीफ फसलों के लिए देश के 400 जिलों में डिजिटल क्राॅप सर्वे किया जाएगा जिसमें छह करोड़ किसानों की खेती और उनकी जानकारी दृढिकसान और खेती रजिस्ट्रेशनह में शामिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती पर जोर दिया गया है और इसके लिए गांव में बायो रिसोर्स सेंटर के माध्यम से मदद उपलब्ध कराई जाएगी ताकि बड़े स्तर पर उत्पादकता का काम होने के

साथ ही आपूर्ति चेन को मजबूत किया जाएगा। सरकार राज्यों के साथ मिलकर कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में डिजिटल प्रक्रिया को अभियान के रूप में लिया जाएगा। सिलक को बढ़ाने तथा इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए उत्पादकता, रिसर्च और विकास की सतत प्रक्रिया के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने तथा कृषि रोजगार को बढ़ाने को महत्व दिया जाएगा। बड़े स्तर पर बेराजगारी को खत्म करने के लिए रोजगार के अवसर जुटाए जाएंगे।

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के महत्व पर जोर देते हुए घोषणा की कि अनुसंधान और विकास पहलों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा, विशेष रूप से दालों और तिलहनों के उत्पादन, भंडारण और विपणन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, हम उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेंगे। इस पहल का उद्देश्य सरसों, मूँगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। उन्होंने कहा, अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुसार सरसों, मूँगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीति बनाई गई है।

कृषि के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा, सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए बजट में प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर प्रमुख उपभाग केंद्रों के करीब विकसित किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम संग्रह, भंडारण और विपणन सहित सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे।

कृषि के लिए तीन साल की योजना की घोषणा

सीतारमण ने कहा, कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए तीन साल की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य किसानों और उनकी भूमि को व्यापक रूप से कवर करना है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार 3 साल में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी

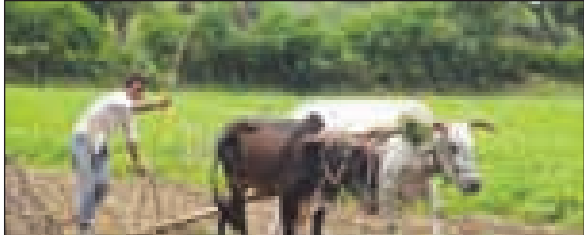


ढांचे की सुविधा प्रदान करेगी। इस वर्ष के दौरान खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण 400 जिलों में किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा, छह करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा। पांच राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की सुविधा दी जाएगी। जिसमें जलीय कृषि के तहत बजट में झिंगा पालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। झिंगा पालन और निर्यात के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से आगे बढ़ाना लक्ष्य

वित्त मंत्री ने कहा कि, सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक नई राष्ट्रीय सहयोग नीति पेश की जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से आगे बढ़ाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना नीति का लक्ष्य होगा। इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से आगे बढ़ाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

भूमि संबंधी सुधार का काम अगले तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य



नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केन्द्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार का काम अगले तीन वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इन सुधारों में भूमि प्रशासन, योजना और प्रबंधन तथा शहरी योजना, उपभोग और निर्माण संबंधी कानून शामिल होंगे। सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में विशिष्ट भूखंडों की पहचान की जाएगी। इसके साथ साथ भू-खंडों का डिजिटलाइजेशन कर

स्वामित्व के अनुसार जमीन और किसानों का पंजीकरण किया जाएगा इससे ऋण देने में असानी होगी तो कृषि सेवाएं भी सुगम होंगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि शहरी इलाकों में भूमि संबंधी किट्टों का जीआईएस मैपिंग कर डिजिटलीकरण किया जाएगा। संपत्ति अभिलेख प्रशासन, अद्यतनीकरण और कर प्रशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता बढ़ेगी

7,651.80 करोड़ रुपये आवंटित

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय तटरक्षक बल को 7,651.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आवंटन से 6.31 फीसदी अधिक है। इसमें से 3,500 करोड़ रुपये केवल पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने हैं, जिससे उभरती समुद्री चुनौतियों से निपटने और अन्य देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए आईसीजी के शस्त्रागार में और अधिक ताकत आएगी। इस आवंटन से तेज गति से चलने वाले गश्ती वाहनों, इंटरसेप्टर, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली और हथियारों के अधिग्रहण में सुविधा होगी।

रणनीतिक सीमावर्ती बुनियादी ढांचा होगा

सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को 6,500 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आवंटन से 30 फीसदी और वित्त वर्ष 21-22 के आवंटन से 160 फीसदी अधिक है। इस वर्ष के वित्तीय प्रावधान से सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे लद्दाख में 13,700 फीट की ऊंचाई पर न्योमा एयरफील्ड का विकास, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत के सबसे दक्षिणी पंचायत तक स्थायी पुल संपर्क, हिमाचल प्रदेश में 4.1 किलोमीटर की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शिंकू ला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश में नेचिपु सुरंग और कई अन्य परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाएगा।



रक्षा के लिए खोला खजाना सेना के आधुनिकीकरण पर जोर

बजट में 6,21,940 करोड़ रुपए का आवंटन

नयी दिल्ली। सरकार ने वर्ष 2024-25 के आम बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए अब तक का सर्वाधिक 6 लाख 21 हजार 940 करोड़ रुपये का आवंटन किया है जो कुल बजट का 12.9 प्रतिशत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इस बार रक्षा मंत्रालय के लिए सर्वाधिक 6,21,940.85 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो इस वर्ष के शुरू में आये अंतरिम बजट में किये गये रक्षा क्षेत्र के प्रावधान के करीब करीब बराबर ही है। वर्ष 2023-24 में रक्षा मंत्रालय का आवंटन 5,93,537.64 करोड़ रुपए था। इस वर्ष के रक्षा बजट में पूंजीगत



व्यय के लिए 172000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि इससे सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए

सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के कार्य में तेजी आयेगी। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और नवाचार तथा छोटी इकाइयों को प्रौद्योगिकी समाधान तथा उन्नयन के लिए आईडैक्स योजना के तहत 518 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट में रक्षा पेंशन मद में 141.205 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि यह आम बजट देश को उत्कृष्ट , समृद्ध और आत्मनिर्भर दृढविकसित भारतह बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि समावेशी और तेज गति वाले विकास की दृष्टि से यह बजट भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देगा।

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा बलों को पूंजीगत मद में बजटीय आवंटन 1.72 लाख करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2022-23 के वास्तविक व्यय से 20.33 फीसदी अधिक है और वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित आवंटन से 9.40 फीसदी अधिक है। बढ़ा हुआ बजट सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक तकनीक, घातक हथियार, लड़ाकू विमान, जहाज, पनडुब्बियां, प्लेटफॉर्म, मानव रहित हवाई वाहन, ड्रोन, विशेषज्ञ वाहन आदि से लैस करने के उद्देश्य से नियोजित पूंजीगत अधिग्रहणों पर वार्षिक नकद व्यय की आवश्यकता को पूरा करेगा। वित्त वर्ष के दौरान घरेलू उद्योगों के माध्यम से खरीद के लिए आधुनिकीकरण बजट का 75 फीसदी हिस्सा यानी



1,05,518.43 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। सेनाओं की ऑपरेशनल क्षमता सशस्त्र बलों को हर समय युद्ध के लिए तैयार रखने के मकसद से सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इस मद में 92,088 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो वित्त वर्ष 2022-23 के बजटीय आवंटन से

रक्षा पेंशन बजट बढ़ाया गया

रक्षा पेंशन के लिए कुल बजटीय आवंटन 1,41,205 करोड़ रुपये है, जो 2023-24 के दौरान किए गए आवंटन से 2.17 फीसदी अधिक है। यह बजट लगभग 32 लाख पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन पर खर्च किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय को आवंटित राशि वित्त वर्ष 2022-23 के आवंटन से लगभग एक लाख करोड़ रुपये (18.43 फीसदी) अधिक है और वित्त वर्ष 2023-24 के आवंटन से 4.79 फीसदी अधिक है। इसमें से 27.66 फीसदी हिस्सा पूंजी में, 14.82 फीसदी हिस्सा जीविका और परिवारलन तैयारियों पर राजस्व व्यय के लिए, 30.66 फीसदी वेतन और भत्तों के लिए, 22.70 फीसदी रक्षा पेंशन के लिए और 4.17 फीसदी रक्षा मंत्रालय के तहत नागरिक संगठनों के लिए है।



बजट से टूट गयीं उम्मीदें

मौदी सरकार-3 के पहले पूर्ण बजट से कई वर्गों की उम्मीदें टूट गयीं। खासकर बरेजोगारों और किसानों को निराशा हाथ लगी है, जबकि उम्मीदों की जा रही थी कि इस बार सरकार बरेजोगारों पर फोकस करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को मौदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट से देशवासियों की उम्मीदों का ज्वार चरम पर था, लेकिन कई वर्गों को इसमें निराशा हाथ लगी। दुनिया में सबसे तेजी से आर्थिक विकास कर रहे भारत के लिए बरेजोगारों सबसे बड़ी चुनौती है। भारत उन देशों में शामिल है, जहाँ बरेजोगारों की दर सबसे ज्यादा है। देश की इकॉनमी तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम उसके मुताबिक नौकरियाँ पैदा करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन आज पेश बजट में विकराल होती बरेजोगारों की समस्या से निपटने के लिए कोई खास घोषणा नहीं की गई है। हालाँकि रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के तहत तीन योजनाओं की घोषणा की गई है लेकिन बरेजोगारों की बढ़ती फौज के लिए यह काफी है। बजट में कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की घोषणा हुई है। लेकिन किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्टेड प्राइस (एमएसपी) को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। साथ ही पीएम किसान यानी किसान सम्मान निधि की रकम भी नहीं बढ़ायी गयी है। माना जा रहा था कि सरकार इस रकम को दोगुना कर सकती है। अभी इस योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। टेक्सपेयर्स को इस बजट से भारी उम्मीद थी। खासकर सबसे ज्यादा टेक्स देने वाले और खर्च करने वाले मीडियल क्लास को ज्यादा राहत नहीं दी गयी है। न्यू टेक्स रजिमी में स्टैंडर्ड डाइवक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। सिद्धांत ही न्यू टेक्स रजिमी में टेक्स स्लेब में बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री का दावा है कि इससे 10 लाख रुपये से ज्यादा वेतन पाने वालों को सालाना 17,500 रुपये तक की बचत होगी। लेकिन पुराने टेक्स रजिमी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले दिनों रेलवे को कई बड़ी घुंटेदानीओं का सामना करना पड़ा है। पिछले साल जून में ओडिशा में, पिछले महिने बंगाल और बिहार सीमा पर और हाल में उत्तर प्रदेश के गाँडा के पास रेल हादसे हुए। इसलिए माना जा रहा था कि बजट में रेलवे के इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारे पर जोर दिया जाएगा, लेकिन बजट में इस तरह का कोई एलान नहीं किया गया। साथ ही वंदे भारत, अमृत भारत और बुलेट ट्रेन के बारे में भी कोई घोषणा नहीं हुई। शेरव बाजार को इस बजट से खासी उम्मीदें थीं। निवेशक खासकर कैपिटल गेन टेक्स को व्यावहारिक बनाने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन बजट ने उन्हें जोर का झटका दे दिया। कैपिटल गेन टेक्स के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह कुछ चुनिंदा असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टेक्स बढ़ाकर 20 प्रतिशतकर दिया गया है। इससे बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। हालाँकि कहा जा सकता है कि यह पाँच महिने का ही बजट है, फिर भी इस बजट ने उत्साह नहीं बढ़ाया।

सामयिकी

कुछ भी करना, आत्महत्या न करना

सुंदर चंद ठाकुर

मृत्यु में दो दिन पहले बहुत ही मार्मिक और उतनी ही वीर्यस घटना देखना को मिली। एक पिता और पुत्र ने पैसें का तींगी से परेशान होकर एक साथ लोकल के आगे आकर आत्महत्या कर ली। किसी ने इस घटना का विडियो बना लिया। इस विडियो को देखते हुए एक क्षण को रूह कांप जाती है। जिस तरीके से 60 साल के पिता और 30 वर्षीय बेटे ने अपना आत्महत्या को अंजाम दिया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई उनके जीवन में पैसा कमाने, उधार चुकाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे? क्या वे थोड़े धैर्य से थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा जिगर के साथ जिंदगी से लड़ते हुए अपना तकदीर नहीं बदल सकते थे? बिल्कुल बदल सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन का नाम ही संघर्ष है। मनुष्य जीवन के इतिहास में जिए, तो वहां मनुष्य के सास और जीवतवा की तमाम कहानियाँ पढ़ने को मिल जाऐंगी। असल में मनुष्य जीवन का अर्थ ही संघर्ष है। बिना संघर्ष के जीवन कैसा। कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो सकता है, बहुत नाम और पैसे वाला। उसके पास बहुत ताकत भी हो सकती है। लेकिन उसे भी जीवन के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। उसे भी अपने पैसे को सही जगह लगाने के बारे में सोचना पड़ता है, उसे भी बीमारियों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। जीवन की ख़ास बात यह है कि यह हर पल बदलता रहता है। यहाँ श्रेष्ठ, यशस्वी की दशा और दिशा हर गुजरते पल के साथ बदलती है। एक व्यक्ति जो आज राजा है, कुछ प्रजा बन जाता है। अमीर गरीब बन जाता है। जवान बुढ़ा हो जाता है। ऐसे ही किस्मत का मारा, थका-हारा दोबारा उठ खड़ा होता है। कमजोर ताकतवर बन जाता है। ये सारे बदलाव मन के संस्करणों से होते हैं। एक खिलाड़ी संकल्प करता है कि वह टीम को जिताएगा और वह लॉर्मन यमाल की तरह हैरान करने वाला गोल करके फ़्रीस को पारस कर देता है। एक ऑटो वाले का बेटा-बेटी आईआईटी, आईआईएम या आईएफए के एजाम पास कर लेते हैं। एक सुदूर गांव में खेती-बाड़ी कर रहे परिपक्व की बेटी ऑलिंपिक में देश को पदक जीत कर देती है। मनुष्य का जीवन सकारात्मक शक्तियों की वजह से निरंतर विकसित होता जा रहा है। जब भी कभी विध्वंस और नष्ट के निर्माण का विकल्प होगा, मनुष्यता निर्माण को ही चुनेगी। एक छोटे बच्चे के भीतर जो जीवन भरा हुआ है, उस जीवन के खिलाने के लिए सृष्टि कुछ भी करेगी। कुछ भी। क्योंकि जीवन का स्थान हमेशा मृत्यु से ऊपर रहता है। जीवन के लिए कुछ भी किया जाए, वह कम है। किसी की स्थिति आखिर कितनी खराब हो सकती है। एक बार एक बेरोजगार युवक एक संन्यासी के पास जाकर बोला- मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। संन्यासी ने उसे सिर से पैर तक देखते हुए पूछाझ कोई मूल्य नहीं, तो अपना एक हाथ मुझे दे दो। मैं तुम्हें उसके मुँहमें गमन दिला दता हूँ। युवक उल्टे पैर भाग गया। हमारे पास एक अमूल्य जीवन है। इसे पैसें, दुख-तकलीफ, सुख-सुविधाओं में मत तोलो। इस जीवन से तुम चाहो, तो परम सत्य को पा सकते हो। इससे तुम स्वयं ब्रह्म में बदल सकते हो। इसे याद रखना। कुछ भी करना, आत्महत्या मत करना।

**ललित मोहन बंसल**

भारत और अमेरिका के बीच सामरिक, ट्रेड और व्यापार संबंधी नीतियों का भारतीय अमेरिकी मतदाताओं पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में चीन से बढ़ते आयात और घटते निर्यात की पृष्ठभूमि में दस से बीस प्रतिशत सीमा शुल्क लगाकर चीनी कंपनियों को निरुत्साहित किया था। इससे दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों में दरार आ गई थी।

कमला हैरिस ट्रंप को हरा चुनाव जीत सकती हैं, बशर्ते...



नहीं आ पा रहे हैं।
अमेरिकी समाज में प्रगतिशील वाम और मध्यमार्गी डेमोक्रेट के पास 53-54 प्रतिशत भाग है। इनमें अधिकतर निम्न और निम्न मध्यम आय वर्ग की एकल महिलाएँ हैं, जो अपने सीमित संसाधनों के कारण मतदान में हिस्सा नहीं ले पाती। कमला हैरिस ने पिछले चार वर्षों में अथक परिश्रम, एक महिला को छूने वाले मुद्दों में गर्भपात और इमिग्रेशन पर काम किया है, उससे महिलाओं के एक बड़े वर्ग में कमला हैरिस के प्रति झुकाव बढ़ा है। चुनाव में अभी मात्र 105 दिन का समय शेष है। कमला हैरिस के समुच्च पार्टी नियमों के अंतर्गत पहले नामांकन हासिल करना है और उसके बाद चुनाव प्रचार में एक बड़े फंड की जरूरत है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनावी फंड में मात्र 910 लाख डालर हैं, जो अमेरिकी चुनाव के लिए अत्यंत अल्प राशि है। हैरिस के दोड़ में आते ही बड़े और छोटे फंड देने वाले आगे आ रहे हैं। उन्होंने पहले पाँच घण्टों में खासी रकम जुटाई है। कमला के समुच्च इस समय सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रपति जो बाइडेन के अकस्मात राष्ट्रपति पद की दौड़ में हटने से पैदा हुई परिस्थिति में नामांकन हासिल करने की समस्या है। उनके नामांकन को लेकर पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में बराक ओबामा, प्रतिनिधि सभा की स्पीकर के रूप में दायित्व निभाने वाली नैन्सी पेलेसी तथा सीनेट और प्रतिनिधि सभा में नैन्सी लोलाइड और नेता के रूप में दायित्व निभाने वाली चूक शमथन रे गिबर्नर की देर रात तक कमला के प्रति समर्थन व्यक्त नहीं किया है। इसके बावजूद कमला एक दर्जन से अधिक डेमोक्रेट राब्यू और स्विंग स्टेट में समर्थन हासिल कर पद के

मीमीदवारों में सबसे आगे हैं। कमला हैरिस के पक्ष में वह बात भी जाती है कि उन्होंने पिछले चार सालों में अमेरिका के विभिन्न राज्यों में मूल अश्वेत, लैटिन अमेरिकी, एशियाई अमेरिकी, दूर दराज के गांवों में रहने वाले आदिवासी और निरधन वर्ग के मतदाताओं के साथ साथ पहली बार चुनाव में भाग लेने को आतुर युवक-युवतियों को अपने वोट बैंक के रूप में लक्ष्य बनाकर साधा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव दोस्त निरमावली से होते हैं, जिसके लिए पार्टियां चुनाव आयोग के सहयोग से विधान के मुताबिक निर्वाचक मंडल का गठन करती हैं। इसके अलावा प्राप्ति के दोनों सदनों में सीनेट के अवकाश काप्रस करने वाले एक तिहाई और प्रतिनिधि सभा के 435 सदस्यों का चुनाव भी इसी दिन (5 नवंबर) को होता है। इस बार इन चुनावों पर भारत और चीन सहित दुनिया भर के निग्राह लगी हैं। जो बाइडेन ने चुनाव से हटने का फैसला क्यों किया, वह एक अगरे चर्चा का विषय है। फिहालत कमला हैरिस उनके स्थान पर नामांकन हासिल कर लेती हैं तो उनका मुकाबला डेमोक्रेट ट्रुडेंट लम्प से होगा। और अगर कमला यह चुनाव जीत लेती हैं तो वह अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होगी। इसके पहले हिलेरी क्लिंटन भाग्य आजमा चुकी हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिली थी। कमला हैरिस के समुख बड़ी अड़चनों में सबसे पहले नामांकन, पार्टी के प्राच और केन्द्र स्तर पर नेताओं और चुनाव प्रचार के लिए एक बड़े फंड के साथ ही जो बाइडेन के अपने 56 प्रतिशत वोट बैंक में एक विश्वास पैदा किए जाने की जरूरत है। हालांकि बाइडेन भारतीय अमेरिकी, अश्वेत समर्थन कर चुके हैं। हालाँही कमला, अश्वेत

थिया अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी वोट बैंक ऐसा है जो डॉनारल ट्रंप के पक्षपाती रवैये से बहुत आहत है। एशियन अमेरिकन एवार्डार्थ जस्टिस के एक ताजा सर्वे में कहा गया है कि जो बाइडेन के चार साल पहले 56 प्रतिशत वोट में से मात्र 8 प्रतिशत वोट ही उनसे छिटका है, शेष किन्हीं भी स्थिति में रिपब्लिकन की झोली में नहीं जाएगा। इसी सर्वे में ट्रंप को एशियन अमेरिकी समुदाय के 25 से 31 प्रतिशत मत मिलने की संभावना जताई गई थी। इसमें भारतीय अमेरिकी कुल जनसंख्या का मात्र 1.5 प्रतिशत ही हैं। एशियन अमेरिकन सबसे तेज बढ़ता हुआ समूह है इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इनमें से ज्यादातर मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट देंगे। इनमें 18 से 34 वर्ष आयु वर्ग के मतदाता एशियन अमेरिकन हैं, जिनमें से 68 प्रतिशत युवाओं के मतदान करने की बात कही जा रही है। इस मतदाता वर्ग के सामने मुख्य मुद्दे रोजगार, हेल्थ और मेडिकेयर, महंगाई और मकानों का बढ़ता किराया है। इन मुद्दों को कमला हैरिस पुरजोस तरीके से उठाती रही हैं, इस कारण भी इस वर्ग में उनके प्रसंगिक ज्यादा हैं। दूसरी तरफ 78 वर्षीय ट्रंप के खिलाफ चार आपराधिक मामलों और करीब 92 अन्यायपूर्ण मुद्दों को लेकर डेमोक्रेट मतदाताओं में भी क्षोभ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हृदयमुनिटीबद्ध उपहार मिलने के बाद वह सहज स्थिति में हैं। वह प्रतिद्वंद्वी बाइडेन को स्लोपी और कमला हैरिस को निष्कर्ष देते और अमेरिका ग्रेट अमेन के लिए अपनी ट्रेंट और व्यापार नीतियों से मेड इन अमेरिका जैसे स्लोगान से अमेरिका में चीनी माल के आयात पर अंकुश लगाना चाहते हैं। उन्होंने भारत और चीन में अमेरिकी कंपनियों के हथिये आउटसोर्सिंग पर

प्रतिबंध लगाए जाने की बात कहकर एशियाई अमेरिकी मतदाता वर्ष समूह को नाराज किया है। इसका असर भारतीय और चीनी सौदेबाज पड़ा है। वहाँ पड़ोसी देश मैक्सिको और लैटिन अमेरिकी देश इम्पेरेशन पर कड़ी कार्रवाई को लेकर पहले से दुखी हैं। असल में ट्रंप अपने 85 प्रतिशत कर्जवैयें (डिबॉजिलिफ़ेड) ईसाई समुदाय को बाइडेन बैंक पर निर्भर हैं जबकि अश्वेत, मैक्सिकन और लेस से चौदह प्रतिशत एशियाई वोट बैंक बटोर रहे हैं। पिछले एक माह में करीब एक दर्जन पोलों में सर्वे में कमला हैरिस और ट्रंप अथवा जो बाइडेन के बीच मात्र ढेढ़ से दो प्रतिशत अंकों का अंतर दिखाया गया है। कमला हैरिस ट्रंप से आयु में बीस वर्ष कम, अधिक शिक्षित और कैलिफ़ोर्निया की एक सुलझी हुई अरनी जनरल होने के नाते इस अंतर को दूर करने में सक्षम हैं। कमला हैरिस अपने वरिष्ठ सहयोगी और राष्ट्रपति जो बाइडेन से भले ही उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और देश की सामरिक और विदेश नीति में पारंगत होने के फलस्वरूप ज्यादा योग्य और सक्षम हैं। लेकिन वह ही उनका ही सच है कि जो बाइडेन ही उन्हें अश्वेत, लैटिन अमेरिकी और एशियाई अमेरिकी वोट बैंक को लुभाने के लिए एप राष्ट्रपति बनाने लाए थे। इसीलिए उन्होंने पद की उम्मीदवाजी से हटने के साथ कमला हैरिस को समर्थन दिया है।

भारत और अमेरिका के बीच सामरिक, ट्रेड और व्यापार संबंधी नीतियों का भारतीय अमेरिकी मन्दावताओं पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। ट्रेड ने अपने पिछले कार्यकाल में चीन से बढ़ते आयात और घटते निर्यात की प्रवृत्तियों में दस से बीस प्रतिशत सीमा शुल्क लगाकर चीनी कंपनियों को निरुत्साहित किया था। इससे दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंधों में दरार आ गई थी। इस बार ट्रम्प काइट हाउस में प्रवेश करते हैं और मध्य एशिया में इजराइल के चहेते अमेरिकी में अपने धन कुबेर व्यवसायों से निर्रे प्रगाढ़ करते हैं, तो मुमकिन है इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध और आगे खिंच जाए। इसी तरह वह खाड़ी में तेल के खेल की राजनीति में सऊदी अरब के वोट बैंक को रक्षाने के लिए ईरान, लेबनान और सीरियाई देशों के प्रति कड़ा रुख अपना सकते हैं। अमेरिकी हितों के संरक्षण में चीन और भारत के विरुद्ध ट्रेड और व्यापार के साधन साथ सामरिक नीतियों में बदलाव लाते हैं तो निश्चय रूप से अमेरिका में रहे भारतीय अमेरिकी समुदाय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

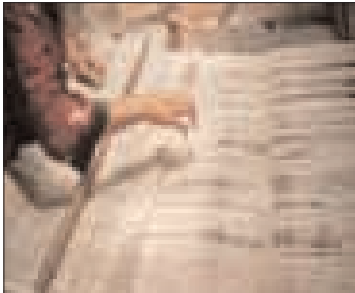
(लेखक, भारतीय मूल के वरिष्ठ पत्रकार हैं,
जो लास एंजेल्स से हैं)

खादी की रिकॉर्ड ब्रिकी और स्वदेशी आंदोलन



डॉ. रमेश ठाकुर

खादी के
वरखों का निर्माण
मशीनों से नहीं
होता। ग्रामीण
स्तर पर ज्यादा
निर्माण होने से
वहां के लोगों को
रोजगार भी मिल
रहा है। इस समय
देश के विभिन्न
जगहों पर
एनएमसी वरखे
लगे हैं। नए
वरखों के लिए
लोग आवेदन भी
कर रहे हैं। खादी
से संबंधित एक
जरूरी सवाल यहाँ
बुलंद करना
जरूरी है।



कहाँ ध्वस्त हो गए हैं। खादी के विभिन्न उत्पादों की बिक्री में 400 प्रतिशत का उछाल हुआ है और इसके उत्पादन में 315 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। खादी नहीं है। यही नहीं, बल्कि रस्तर पर 81 फीसदी नए रोजगार सृजन भी हुए हैं। 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 332.14 फीसदी बिक्री, 267.52 प्रतिशत प्रोडक्शन और 69.75 फीसदी स्वेदरिंग पैदा हुई है। खादी से जुड़े रोजगार ज्वारदार ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा हुए हैं। वहाँ कटाई, बुनाई के कारखानों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएँ अधिक भागीदार हुईं हैं।

बरहलाल, खादी के कपड़ों में अनायास देशवासियों का रुचि लेता, निरर्थक बड़े बदलावों और संकेत देता है। कहावत है कि ओल्ड इज गोल्ड। खादी की अचानक बढ़ी मूल्यवादी बिक्री ने ये कहावत भी अचिरार्थ कर दी है। शायद ठंडे कपड़ों और आधुनिक ककाचों से लोग अब ऊबने लगे हैं। तभी, लोग फिर से अपनी जमीन की ओर मुड़ने को मजबूर हुए हैं। आँकड़ों के मुताबिक वर्ष 2003-2013 में खादी का कारोबार 26109.08 करोड़ रुपये था, जो 2014-2023 में छलांग लगाकर 9556.68 करोड़ रुपये तक जा पहुँचा। इनमें खादी के निर्मित कपड़े

अन्य उत्पादों से कहीं अधिक हैं। जनमानस का खादी की ओर मुड़ना निश्चित रूप से स्वदेशी अभियान को पंख लगाने जैसा है। मौजूदा संस्करण ने करीब दशक भर से स्वदेशी अभियान की अलख जगाई हुई है। इस लिहाज से खादी के कारोबार में भयंकर बिक्रमवाली का होना उनके अभियान की सफलता पर मुहर लगाने जैसा है।

निर्धन रूप से खादी में अब प्रत्येक वर्ग की रूचि बढ़ी है। खादी का कपड़ा खास है जो किसी धर्म-समुदाय से वास्ता नहीं रखता। प्रत्येक सच्चे देशभक्त का अपना देशी कपड़ा है। फिर माल्यसंख्य हों, सिख हों, साधु हों या पांचों अल्पसंख्यकों के, शिक्षित युवा-युवती। सभी ने खादी को अपना आरंभ कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दशकों पहले महान्या गांधी ने स्वदेशी खादी उत्पादों को अपनाने की ये देशवासियों के भीतर अलख जगाई थी उसका असर अब कहीं दिखा है। खादी आंदोलन, एक सामाजिक-सांस्कृतिक आश्वासन, जो गांधी द्वारा मई-1915 में सत्याग्रह आश्रम से शुरू किया गया था, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती आश्रम के नाम से लोकप्रिय है। गांधी युग में खादी के कपड़े

लोगों के सिर चढ़कर बोलते थे। धारणा पहले कुछ ऐसी थी कि सच्चा हिंदुस्तानी मतवाल खादी को अपनाने वाला। गांधी ने ताऊ खादी को अपनाया। दूसरों को भी हमेशा खादी पहनने को ही कहा। खादी का बोलबाला कभी कम नहीं होगा। आज खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अंगत नौ उत्पादन केंद्र पूरे भारत में मौजूद हैं, जहां चरखे से धागे का निर्माण होता है। बुनकर खादी के वस्त्र बनाते हैं जिनके लिए खादी एग ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित दर पर श्रमिकों का भुगतान किया जाता है। बनारस में आज भी वस्त्र स्तर पर निजी रूप से बुनकरों द्वारा खादी के बड़े तैयार किए जाते हैं। वहां कार्ग, पांच लाख लोग इस कार्य में जुड़े हैं। खादी को अपनाने के लिए जब से सरकारी स्तर पर स्वदेशी अभियान छेड़ा गया, तभी से इन बुनकरों की बरल्ले-बरल्ले हो गई। अब इन्हें इस्लाम बड़ी-बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलते हैं। इस आधार पर ही खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें लाखों लोगों को स्वरोजगार मिलने की बात कही है।

महात्मा गांधी ने 1920 के आखिरी महिने में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया था, जिसमें उन्होंने खादी को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। महात्मा गांधी ने तब समूचे भारत में ग्रामीण स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए खादी की अंतर्दाल को बढ़ावा दिया था। इस प्रकार खादी स्वदेशी आंदोलन का एक अविनाश और प्रतीक बन गया था। वैसे, देखा जाए तो खादी महज एक वस्त्र मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के अस्तित्व, परंपरा, पहचान और संस्कार की है। हम जब खादी धारण करते हैं, तो ऐसा एहसास होता है जैसे मानो अपनी संस्कृति को हम प्रदर्शन कर रहे होते हैं। खादी हमारी

पारंपरिक बोहरर समान है जिसे मौजूदा वक्त में देखावासियों ने आत्मनिर्भर नभ्रभरत के मंत्र को पहचकन ही इसके कारोबार में भारी उभरल लववाया है। खरदी को नुन आजार सदस से लेकर लोबल बाजार करन सुनाई देती है। यही कारण है कि खरदी के कारोबार ने देश में पहली मंत्रवा डेड लाख करोड़ के कारोबार को पकिया है जिसने सेना आधुनिक फास्ट मूविंग कंजुमर गुडरा यानी एफएमसीजी कंपनियों को पछे छोड़ा है। खरदी के नए कीर्तिमान स्थापित करणे का मालव है, केंद्र सरकार का स्वदेशी अभियान और आत्मनिर्भरता की अप्पल का असर दिखराना। इसे नया रिफॉर्ड है कि कहेन, जब बीती 26 जनवरी को दिल्ली के कर्नाट प्लेस स्थित खरदी स्टोर में एक दिन की बिक्री 1.29 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। खरदी पहनना ब्रांडेड कपड़ों के मुकामले हमेशा से सुलभ और सरल माना गया है। इसका सेब से सस्ता और मंहें से महंगा कपड़ा हाथों से ही बना जाता है।

खादी के वस्त्रों का निर्माण यशीनों से नहीं होता। ग्रामीण रोज़ रोज़ पर ज्यादा निर्माण होने से वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इस समय देश के विभिन्न जगहों पर एनामसी चरखे लगे हैं। यहाँ चरखों के लिए लोग आवेदन भी कर रहे हैं। खादी से संबंधित एक जरूरी सवाल यहाँ बुनकर पहना जरूरी है। दरअसल, खादी के कपड़े अब कलेक्शन के मुकाबले उनसे सस्ते नहीं रहे। याम भरपुर खेले हैं। बावजूद इनके खरीदारों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है। सरकार अगर खादी के मामले में कुछ कटौती कर दे तो कारोबार में और उछाल आएगा, क्योंकि खादी के दाम जिन्हें सस्ता से आसामान छू रहे हैं, वो कइयों की पहुँच से दूर है। इस ओर ध्यान देने की केंद्र सरकार को जरूरत है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)



आरके सिन्हा

यदि देश की जनता के दिल में आईएएस पदाधिकारियों के प्रति स्वाभाविक रूप से सम्मान और आदर का भाव नहीं रह जाएगा, तो कोई भी आईएएस प्रशासन कर ही नहीं पाएगा। आईएएस अधिकारियों से अपनी भूमिकाओं में निष्पक्षता और अखंडता का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है।

उन्हें एहसास नहीं था कि आईएसएस अफसर बनने का मतलब जसवंत जसवांवा होता है। इसके बजाय, उसने इस पद को हासिल करने के बाद अपनी बूढ़ी शान दिखानी शुरू कर दी। उसने कार, सुरसज्जित कार्यालय और कर्मचारियों—उसी का सुविधाओं की मांग की। चूँकि प्रोबेशनर्स इन लाभों के हकदार नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी लाभ नहीं दिया गया। इसलिए, उसने अपनी दैनिक जरूरतों के लिए एक लज्जती कार 'क्रिएए प्र' ली। इससे भी बुरा यह है कि उन्होंने कार को छत पर नीली बॉकन लाइट भी लगाईं। बॉकन लाइट के इस्तेमाल को लेकर निम्न है कि हर कोई ऐसी लाइट नहीं लगा सकता, जिसके कार्यात्मक उद्देश्य आवश्यक नहीं हैं। एम्बुलेंस वाहन पर ऐसी लाइट वाहन की तेज गति को सुविधाजनक बनाने के लिए होती है। पूजा का चयन दो विशेष श्रेणियों के तहत किया गया था। एक, वह ओबीसी के गैर-क्रीमी वर्ग से संबंधित है। यह स्वयं ही सौंदर्य है, यह देखते हुए कि उनके पिता एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे। फिर वह गैर-क्रीमी लेयर में कैसे चुनी गईं। वह निश्चित रूप से गरीब व्यक्ति नहीं थीं। उनके परिवार के पास पर्याप्त जमीन है जो निश्चित रूप से उन्हें एक अलग



आर्थिक श्रेणी में रखेगी। पूजा ने यह भी दावा किया था कि उसकी एक अलग तरह की शारीरिक स्थिति है, जो उसे विकलांग कोटे के तहत आरक्षित सीट के लिए हकदार बनाती है। यूपीएससी और कर्मिक विभाग द्वारा विकलांगता के संबंध में कुछ तय दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं। एक व्यक्ति जिसे एक आँख में दृष्टि नहीं होती है, उसे 'विकलांग' नहीं माना जाता है, यदि दूसरी आँख हर तरह से ठीक है।

मैं इस के बारे में तब जाना जब परीक्षा एक मिनट के पुरे ने सजिल सजवा परीक्षा नहीं। बचपन में, उसके एक भाई ने उसकी दाहिनी आँख में कंपास डाल दिया था, जिससे वह आंशिक रूप से दृष्टिहीन हो गया था। वह विकलांग कोटे के तहत आरक्षण के लिए योग्य

नहीं होता, अगर उसकी दूसरी आँख नहीं होती। उसकी 'सामान्य' आँख में आँसिक अंधापन था। इस तरह वह रेलवे सेवा के लिए चुना गया, जहाँ वह अलग एक निम्नस्तर पर पड़े। पूजा खेडकर के मामले में, वह लोकोमोटिव डिपार्टमेंट की दावा करती है, जो उसकी बाहों और पैरों के चलने में बाधा उत्पन्न करती है। डॉक्टर और तकनीशियन आसानी से कमी का आकलन कर सकते हैं। उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एमए) के प्रोक्तल बोर्ड के सामने खुद को प्रस्तुत करना चाहिए था, जो वह प्रमाणित करता था कि वह विकलांग श्रेणी में शामिल करने के लिए योग्य है या नहीं।

किसी न किसी बहाने से, वह बोर्ड के सामने पेश नहीं हुई। एक बार नहीं

बालिक पांच बार। वह उन अस्पतालों से विकलांगता का उचित प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं कर सकी थीं जिन्से उसने कथित तौर पर संपर्क किया था। यह भी रिकॉर्ड पर है कि उसने 2007 में एक मेडिकल कॉलेज में शामिल होने के दौरान पूर्ण फिलिज में शामिल जमा किया था। उल्लेखनीय बात यह है कि कार्मिक विभाग ने उसे मसूरी में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने और मेडिकल में शेक-अप पास किए बिना आईएसएस में शामिल होने की अनुमति दी। यहां कोई गंभीर गलती हुई है, जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा और सही और निष्पक्ष जांच के बाद इसके लिए दोषी अधिकारी या अधिकारियों को दंडित तो करना ही होगा।

केंद्र सरकार ने एक मेडिकल परीक्षा का आदेश दिया है जिसके लिए उसने एक व्यक्तिगत सप्लिक निवृत्त की है, जो यह साबित करेगी कि क्या वह किसी भी विकलांगता से पीड़ित है। अगर उसने नख्बे नहीं दिखाए होते, तो वह सेवान में नहीं रहती। इससे कांड के बाद वृषीएससी की कार्यपालनी भी अच्छी रोशनी में नहीं दिखता है।

अपने भी गंभीर बात यह है कि पूजा अपने जिला मजिस्ट्रेट जिससे अधीन वह प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी उसने आदेशों की अनदेखी करती थी। यह

सरकारी सेवा में एक गंभीर आरोप है। इस बीच, तेलंगाना में एक आईएएस अधिकारी के बारे में भी रिपोर्ट आई हैं, जो कुछ विकासगताओं के आधार पर सेवा में शामिल हुए। उदाहरण के लिए, उन्हें कथित तौर पर पोलियो का हमला हुआ है। लेकिन घोड़े की सवारी और साइकिल चलाते हुए उनके वीडियो यह तो नहीं बताते कि वे कभी पोलियो के शिकार थे? इससे यह सवाल उत्पन्न है कि क्या सिविल सेवाओं में किलालांग श्रेणियों के तहत रिक्तियों को भरने में मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाता है। लगाना तो यही है कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और पिछले २०-२५ वर्षों में विकासगताओं के आधार पर चुने गए ऐसे सभी मामलों को जांच के दायरे में लाने की आवश्यकता है। आईएएस, जिसे अक्सर "भारत के इम्पलूमेंट" के रूप में जाना जाता है, यह उपाधि सरदार वल्लभभाई पटेल, "भारत के लौह पुरुष" से प्राप्त करता है। उन्होंने नव स्वतंत्र भारत की एकता और स्थिरता बनाए रखने में सिविल सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया। आईएएस राष्ट्र के प्रभावशाली शासन के लिए आवश्यक, सरसमेय प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है। इस

सत्ता में भर्ती में कोई भी समझौता देश के हितों का गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है। यदि देश की जनता के दिल में आईएसएस पदाधिकारियों के प्रति स्वाभाविक रूप से सम्मान और आदर का भाव नहीं रह जाएगा, तो कोई भी आईएसएस प्रशासन कर ही नहीं पाएगा। आईएसएस अधिकारियों से अपनी भूमिकाओं में निष्पक्षता और अखंडता का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। उनके फैसले लाखों लोगों के जीवन और देश की सम्पूर्ण स्थिरता को प्रभावित करते हैं। निष्पक्षता बनाए रखकर और कानून के शासन का पालन करके, आईएसएस अधिकारी यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम निष्पक्ष रूप से और प्रभावी ढंग से लागू किए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया से समझौता पक्षपात ला सकता है और कानून के शासन को कमजोर कर सकता है, जिससे अस्थिरता और जनता का विश्वास कम हो सकता है। पूजा खेडकर का मामला इस बात की गवाही है कि हमारे देश में फर्जी प्रमाणित दिखाकर मलाई खाने का खेल खूब चल रहा है, जिसे तत्काल बंद किए जाने की आवश्यकता है।

(लेखक, वरिष्ठ सांपदक, संतंभकार और पूर्व सांपद है।)



पत्नी व बच्ची की गला दबाकर हत्या, गिरफ्तार

बुढ़मू थाना क्षेत्र की घटना
मृतका के पिता ने लगाया
है दहेज हत्या का आरोप,
प्राथमिकी दर्ज
नव प्रदेश संवाददाता

रांची। बुढ़मू थाना की पुलिस ने दोहरे हत्याकांड में मृतका के पति डब्लू यादव को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्त में आया आरोपी अभियुक्त बुढ़मू के साडम गांव का रहनेवाला है। पुलिस टीम में पुअनि रामजी कुमार, थाना प्रभारी, बुदमू थाना, पुअनि रवि रंजन कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

वया है मामला
पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर सोमवार की सुबह बुढ़मू थानानर्गत स्थित साडम तालाब से एक महिला और एक बच्ची का शव बरामद की थी। स्थानिय चौकिदार एवं ग्रामिणों



के द्वारा मृतिका का पहचान 25 वर्षीय संगीता देवी, पति-डब्लू यादव (साडम, थाना-बुढ़मू), और उसकी ढाई वर्ष की बेटी अनुष्का के रूप में की गई थी। मौके पर मृतिका के पति द्वारा भी अपनी पत्नी और

बेटी को पहचान की गई थी। पुलिस अनुसंधान में शव को देखने से प्रथम दृष्टया दोनों की गला दवाकर हत्या करने के उपरांत शव को तालाब में फेंकने का मामला प्रति्त हुआ था। तत्पश्चात पुलिस ने मृत्यु समिक्षा

रिपोर्ट तैयार कर दोनों शव को परिक्षण हेतू रिम्प, रांची भेजा गया।
पिता ने लगाया है दहेज हत्या का आरोप
वहीं इस घटना में बुढ़मू थाना क्षेत्र

के कोटारी गांव में रहनेवाले मृतिका के पिता डहरू महतो के द्वारा मृतिका के पति डब्लू यादव और ससुराल वालों के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज के कारण हत्या करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ थाने में लिखित प्राथमिकी दर्ज करते हुये पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुये संदेह के आधार पर मृतिका के पति-डब्लू यादव को पकड़कर पृछताछ की गई। जिसमें आरोपी पति ने घटना में अपनी सलिलपा स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतिका के शव को तलाब तक ले जाने वाली घटना में प्रयुक्त एक प्लास्टिक का काला टब, एक गुलाबी, गिला, हरा रंग का कंबल व साईकिल को जब्त की है।

मायके से पत्नी व बच्ची को साथ लेकर पति आया था घर

पुलिस के अनुसार मृतका के पिता ने बताया कि आरोपी पति उबलू यादव उसकी बेटी व बच्ची को दिन में घर से विदाई कराके अपने घर लेकर गया था। उसी दिन रात में आरोपी पति ने दोनों की घर में गला दबाकर हत्याकर शव को तलाब में फेंक दिया था।

पत्नी को मोबाइल पर बातचीत करते देख पति हुआ था आगबबुला

पुलिस पृछताछ में आरोपी पति ने बताया कि मायके से ससुराल आने के बाद उसकी पत्नी किसी से मोबाइल पर बातचीत कर रही थी। इसी बातचीत में दोनों में विवाद काफी बढ़ गया, जिसमें उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। पत्नी की हत्या करते देख बच्ची ने देख लिया था। पकड़े जाने के डर से उसकी भी हत्या कर दी।

आत्मनिर्भर युवा पर केंद्रित है यह बजट : रमेश सिंह



नव प्रदेश संवाददाता

रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को पेश मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इसे युवाओं के लिए उज्ज्वल भविष्य वाला बजट बताते हुए भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रमेश सिंह ने कहा कि यह बजट विकसित भारत का बजट है, यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति को सशक्त करने का बजट है, इस बजट में सरकार ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। इस बजट ने माध्यम से

सरकार ने विकसित भारत की बुनियाद को मजबूत करने का काम किया है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और अब यह बजट लोगों को सशक्त करेगा।युवाओं को नये अवसर प्रदान करेगा।

प्रमंडलीय आयुक्त, रांची ने प्रमंडलीय जिला के उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ की समीक्षा बैठक आयोजित

वीआईपी, 80 प्लस व 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं की तैयार होगी मतदाता सूची

विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या बनाने का निर्देश
शत प्रतिशत मतदाताओं का वोटर कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश
विधानसभावार हर घर का सर्वेक्षण कार्य करने का निर्देश
नव प्रदेश संवाददाता



जेंडर व सेक्स वर्कर सहित कुल मतदाताओं की संख्या की जानकारी ली। आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि विधानसभा क्षेत्रवार की ईआरओ, ईआईआओ, बीएलओ, सुपरवाईजर के पदनाम, स्वीकृत पद सहित रिक्त पद का विवरण उपलब्ध कराया जाए, साथ ही विधानसभावार शिक्षक,पारा शिक्षकों की संख्या व बीएलओ की संख्या पदस्थापन के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। आयुक्त ने कहा कि प्रमंडल के सभी पांचों जिला के मतदाता का जेंडर रेशियो शहरी क्षेत्र में सभी घर का सर्वेक्षण कर

बीएलओ,सुपरवाईजर द्वारा सर्वेक्षण स्टिकर चिपकाने संबंधी निर्देश उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने पदाधिकारियों से कहा कि विशेष अभियान दिवस दिनांक 27 - 28 जुलाई 2024 और 3 - 4 अगस्त 2024 को चलाया जायेगा जिसमें मतदाता सूची में दूसरथ क्षेत्र के जनसमूह का निबंधन संबंधी कार्रवाई की जाए। 30 जुलाई 2024 को सभी रैनबसेरों,आश्रय गृहों में अवस्थित नागरिकों का निबंधन सुनिश्चित हो। दिनांक 31 जुलाई 2024 पात्र

दिव्यांगजनों का निबंधन एवं मतदाता सूची में मार्किंग हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु निर्देश दिया। दिनांक 01 अगस्त को विशेष समूह 85 + आयु के मतदाता का निबंधन हाउस टू हाउस वीजिट संबंधी प्रतिवेदन देने एवं दिनांक 2 अगस्त को सभी पात्र थर्ड जेंडर,सेक्स वर्कर का निबंधन सहित फार्म -6, 6ए, 6बी एवं 8 की प्राप्ति, निर्गत, पेडिंग की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने को कहा गया। वोटर हेल्पलाइन एक्टिवेशन , स्वीप एक्टिवेशन और पब्लिक जागरूकता संबंधी सूचना के साथ लोक शिकायत निवारण सिस्टम संबंधी सूचना, की समीक्षा उक्त बैठक में की गई। समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त के सचिव जुल्फिकार अली, रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा व खूंटी के उप निर्वाचन पदाधिकारी, क्रमशः विवेक सुमन, सुपमा लकड़ा, धीरज कुमार ठाकुर, पवन कुमार महतो व प्रेमचन्द कुमार सिन्हा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

देश का आम बजट अदृशर्शी, झारखंड को निराश किया, स्वतंत्र भारत का सबसे कमजोर बजट एचईसी को उदास किया, निम्न मध्यम वर्ग को कोई विशेष लाभ नहीं इससे बेरोजगारी महंगाई में कोई राहत नहीं मिलेगी : कैलाश यादव

नव प्रदेश संवाददाता
लाभ नहीं मिला, बेरोजगारी,महंगाई जस का तस रहेगा, निम्न मध्यम वर्ग को कोई फायदा नहीं हुआ, गृहणियों कोई राहत नहीं घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल खाद बीज में कोई राहत नहीं, श्रमिको को कोई विशेष लाभ नहीं, भारी उद्योग कारखाना के रिवाइवल के लिए कोई प्रावधान नहीं! शिक्षा चिकित्सा और स्वास्थ में

आशा के अनुरूप कुछ भी नहीं सोशल नेटवर्किंग के देश में तकनीकी संस्थान को बढ़ावा देने का कुछ भी नहीं! भारत एजुकेशनल हब रहा है, दूरदर्शी विजन का अभाव है जिस कारण मल्टीनेशनल कंपनियां अपना पांव पीछे खींच रही है! यह बजट स्वतंत्र भारत का सबसे कमजोर है।

जान मारने की धमकी देने से जुड़े मामले में नौ आरोपित साक्ष्य के अभाव में बरी
नव प्रदेश संवाददाता

रांची। एसडीजेएम आरएस टोपनो की अदालत ने मंगलवार को जान मारने की धमकी देने से जुड़े आठ साल पुराने मामले में टयल फेस कर रहे नौ आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इसमें सिकिंदरी निवासी प्रेमानाथ बेदिया, धनेश्वर बेदिया, हरिनाथ उरांव, कुलदीप बालमुचू, राजेन उरांव, इतवा उरांव, सिलाश उरांव, शिवधर महतो उर्फ नीरज कुमार एवं हजारीबाग निवासी अभय कुमार राय शामिल है। इन लोगों पर अलगगढ़ के तत्कालीन श्रम प्रवर्तन अधिकारी नरेंद्र सिंह को बंधक बनाकर पेड़ से बांध देने और दोबारा गांव में आने पर जान से मार देने की धमकी का आरोप था। तत्कालीन श्रम प्रवर्तन अधिकारी 3 फरवरी 2016 को अलगगढ़ में निर्माणधीन सड़क के देखने गए थे। निर्माण को लेकर वहां के मजदूरों से पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें बंधक बना लिया गया था। घटना को लेकर नरेंद्र सिंह ने सिकिंदरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

महिला थाना ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

नव प्रदेश संवाददाता
रांची। महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी प्राथमिकी अभियुक्त प्रीतम कुमार देव को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दी। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी अभियुक्त बोकारो जिला के सेक्टर-वन स्थित वास्तु विहार का रहनेवाला है। गौरतलब है कि इस मामले में आरोपी अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता की लिखित शिकायत पर महिला थाना में चार जुलाई 2024 को कांड संख्या 43/24 दर्ज की गई थी। कांड दर्ज होने के बाद से आरोपी अभियुक्त फरार चल रहा था।



दुष्कर्म का आरोपी नाबालिग निरुद्ध
रांची। धुर्वा थाना की पुलिस ने मंगलवार को दुष्कर्म करने के आरोपी नाबालिग को निरुद्ध की है। आरोपी नाबालिग के खिलाफ धुर्वा थाना में 26 मई 2024 को पीड़िता की लिखित शिकायत पर कांड संख्या 172/24 दर्ज की गई थी। जिसमें आरोपी अभियुक्त फरार चल रहा था।

25वां तीन दिवसीय सावन मेले का दूसरा दिन

महिलाओं ने मनाया सावन सिंधारा व झूलोत्सव

नव प्रदेश संवाददाता
रांची। अग्रवाल सभा रांची की महिला समिति शाखा के तत्वाधान मे महाराजा अग्रसेन भवन मे आयोजित 25 वां तीन दिवसीय सावन महोत्सव मेले के दूसरे दिन महिलाओं द्वारा सावन सिंधारा एवं झूलोत्सव मनाया गया। इसमें महिलाओं ने खुब मस्ती की। बहू-बेटियों का सिंधारा किया गया। महिलाओं ने सावन के मनमोहक गीतों पर खूब दुमके लगाए, झूला झूलकर खुब आनंद लिया। वहीं अंताक्षरी के साथ ही कई मजेदार गेम्स भी खेले गए। जिसमें जीती हुई महिलाओं को पुरस्कृत किया गया, इस मेले में सभी ने लजीज व्यंजनों का लुप्त उठाया।



सावन महोत्सव मेले में 100 से भी ज्यादा स्टॉल लगे हैं। जिसमें जयपुरिया ज्वेलरी, कोलकाता, बनारस, भागलपुर की ढेरों डिजाइनर कलात्मक साड़ियां,

शादी के लहंगे,एक्सक्लूसिव डिजाइनों में सलवार सूट, बेइशीट, छोटे बच्चों के स्पेशल कपड़े, रंग-बिरंगे नवीनतम राखियां, अलग-अलग शहरों की

स्पेशल सामग्रियों का कलेक्शन, इंडो वेस्टर्न ड्रेस, सजावट के समान, श्रृंगार एवं पूजा की सामग्रियां, लड्डू गोपाल के पोशाक, हस्तशिल्प उत्पाद सामग्री, अचार, पापड़, बड़ी, मुरब्बा, तथा अन्य सामग्रियों की खरीदारी महिलाओं ने जमकर की। मेले की संयोजिका अलका सरावगी ने बताया कि 24 जुलाई को शाम चार बजे मेले के समापन होगा। जिसमें समिति द्वारा मेले के बेस्ट स्टॉल को पुरस्कृत किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए अग्रवाल सभा के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी संजय सर्राफ ने बताया कि कार्यक्रम मे अग्रवाल सभा महिला समिति की संयोजिका रूपा अग्रवाल, नीरा बथवाल, सावन

मेले की संयोजिका अलका सरावगी, सह संयोजिका रीना सुरेखा, अंशु नेवटिया,गीता डालमिया, बिना बबूना, मंजू केडिया, मधु सराफ, सरिता अग्रवाल, प्रीती पोद्दार, मंजू गाड़ोदिया, बीना मोदी, सीमा पोद्दार, शोभा हेतमसरिया, छाया अग्रवाल, प्रीती बंका, उर्मिला पड़िया, लक्ष्मी पाटोदिया, सीमा टांटिया, सुश्री लोबलका, प्रीती फोगला, शशि डागा, सुपमा पोद्दार, बबोिता नारसरिया, अलका अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल, सखा टिबेरवाल जैन, करुणा अग्रवाल, मीरा टिबेरवाल, प्रीति केडिया, जया बिजावत, सुधा अग्रवाल, निर्मला अग्रवाल सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित थीं।

एक नजर

गरीबों को मिला सब्सिडी, अमीरों को मिला रिबेट, मीडिल क्लास टीवी देखो, आपको मिला डिबेट : आदित्य विक्रम जयसवाल

नव प्रदेश/रांची। मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश आम बजट पर प्रोफेशनल्स कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदित्य विक्रम जयसवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गरीबों को मिला सब्सिडी, अमीरों को मिला रिबेट, मीडिल क्लास टीवी देखो, आपको मिला डिबेट। भारत एक कृषिप्रधान देश है, कृषि संबंधित कोई बजट नहीं है, मनरेगा का जिक्र नहीं है। झारखंड में भी हमारा बाबाधाम है, देवडी, रजरप्पा मंदिर है, ट्रिज्म पर कोरिडोर बन सकता था, माननीय प्रधानमंत्री चुनाव के पहले बड़े-बड़े योजनाएं लेकर आये थे भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर। झारखंड पर टाइबल इंकॉनोमी पर क्यों नहीं बात किया गया। एक पैकेज बनाना था। उन्होंने आम बजट पर आगे कहा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है, अपने सहयोगियों को खुश करने का बजट है। कुछ प्रतिशत कांग्रेस मैनिफेस्टो से लिया गया है कुछ पूंजीपतियों को खुश करने के लिए बजट है अबकी बार बाजी मारा है आंध्रा और बिहार। इस लिहाज से आंध्रा और बिहार का बजट है। आने वाले समय में एक मजबूत देश कैसे बने यह बहुत ही चुनौती है। हम सब मिलकर देश निर्माण के लिए काम करना चाहिए। हम सभी व्यापारी को ट्रेड्स को पूंजीपतियों के सोच के साथ आगे बढ़िए और देश को सशक्त बनाएं।

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर दो दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे

रांची। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को समीक्षा करने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर दो दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे । एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मीर सीधे रामगढ़ के लिए रवाना हो गये। मंगलवार को प्रदेश पार्टी प्रवक्ता सोनल शांति ने बताया कि रामगढ़ के रजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित मनोरंजन गृह में कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम और चितरपुर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे।

रिश्वत लेते पुलिस सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार
लातेहार। लातेहार जिले के बरियातू थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो निगरानी की टीम ने मंगलवार को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते रीहाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपित सब इंस्पेक्टर के द्वारा बरियातू थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति को केस में फसाने की धमकी देकर रिश्वत की मांग की जा रही थी। जानकारी के अनुसार बरियातू का रहने वाले एक व्यक्ति ने पलामू निगरानी की टीम को आवेदन देकर कहा था कि उसके भतीजे को पुलिस ने कुछ दिन पहले अफीम तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके बाद बरियातू थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा उसे लगातार धमकी दी जा रही थी कि 3 लाख रुपए रिश्वत दो, नहीं तो अफीम की तस्करी के झूठे केस में फंसा कर जेल भेज देंगे। लगातार दबाव मिलने से पेशेशन वादी के द्वारा पलामू निगरानी की टीम को आवेदन देकर इसकी शिकायत की गयी।

कार्यपालक उभिसंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग,
भवन प्रमण्डल, हजारीबाग

शुद्धि पत्र

एसाद द्वारा सूचित किया जाता है कि अधिलक्ष्यवालीन निविदा आमजन सूचना संख्या-14/2024-25_PR संख्या-329386 Building (24-25). D द्वारा प्रकशित निविदा के पुप सं0-06 का कार्य का नाम –Renovation work for Primary School, Hudurwa, Block-Barkagaon, Hazaribag. एवं पुप सं0-07 कार्य का नाम –Repair for work of Class Room Building of B.C Girls Residential High School at Matwari Block Sador ,District-Hazaribag को जल्दियार्वे कारणवश रद्द की जाती है।

कार्यपालक उभिसंता, भवन प्रमण्डल, हजारीबाग।

PR.NO.336453 Building(24-25).D

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
National Rural Employment Program, Ranchi.

Very Short e-Procurement Notice

e-Tender Reference No. - National Rural Employment Program, Ranchi/RANCHI-132323-24 Date :-

Sl. No.	Name of Scheme	Estimated Amount (Lakh)	Estimate More (Lakh)	BBOQ Cost (Lakh)	Scheme Completion Day	Tools & Plant
1	राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार निरोधक कार्यक्रम (MGNREGS) के तहत नया बांध (New Ban)	2,50,00,000	3,50,00,000	10,000	12Months	सर्वेक्षण उपकरण
2	NAL House construction for the poor (NAL House)	2,50,00,000	3,50,00,000	10,000	12Months	सर्वेक्षण उपकरण
3	राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार निरोधक कार्यक्रम (MGNREGS) के तहत नया बांध (New Ban)	2,50,00,000	3,50,00,000	10,000	12Months	सर्वेक्षण उपकरण
4	राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार निरोधक कार्यक्रम (MGNREGS) के तहत नया बांध (New Ban)	2,50,00,000	3,50,00,000	10,000	12Months	सर्वेक्षण उपकरण
5	Mode of Submission of Tender	Online through www.barkhandtenders.gov.in Start Date 20/07/2024 at 10:00 AM End Date 01/08/2024 up to : 1:00 PM				
6	Date of Publication of Tender on Website	Start Date 20/07/2024 Time : 11:00 AM End Date 01/08/2024 Time : 1:00 PM				
7	Mode online Submission	Start Date 20/07/2024 Time : 11:00 AM End Date 01/08/2024 Time : 1:00 PM				
8	Technical Bid Opening Date	Date 01/08/2024 Time : 11:00 AM				

Officer Inviting Bids

Executive Engineer
National Rural Employment Program,
Ranchi,
Address : National Rural Employment Program,
Vishakh Bharan, Ranchi.

Executive Engineer
National Rural Employment Program, Ranchi.

PR 330386 (NREP) 24-25 (D)

Jharkhand Urja Utpadan Nigam Limited,
(CIN: U40108MH2013SGCO001703)
Office of the Project Manager, SRHP Skidiri,
AT & P.O. -SRIDHRI (PIN Code: 835218) DISTRICT- RANCHI, Jharkhand
E-mail ID :- srhp.skidiri@gmail.com Mob. No. :- 9411707312

Re- TENDER NOTICE

Noted tenders are invited by Office of Project Manager, SRHP Skidiri on behalf of Jharkhand Urja Utpadan Nigam Ltd under Two Bid System i.e. Technical Bid and Financial Bid from reputed, experienced and financially sound bidders/contractors/enterprises/individuals for following items on the terms and conditions mentioned in the tender documents and details of which are as below:-

Sl. No.	MT in	Name of works	Estimate Money to be deposited (Rs.)	Cost of Tender Document (Fee Refundable) (Rs.)	Delivery Period
1	24-JUL-2024	Procurement of Flexible Copper Jumper & its accessories for PTH in SRHP Skidiri.	6,00,000	(750.00 + 10% GST)	30 Days
2	25-JUL-2024	Procurement of Lightning Arrester for PTH in SRHP Skidiri.	8,00,000	(750.00 + 10% GST)	30 Days

- Last date and time for submission of tender paper :- 08.08.2024 upto 04:00 PM.
- Last date and time for submission of tender paper :- 08.08.2024 upto 04:00 PM.
- Bank name and account number :- 08.08.2024 upto 04:00 PM.
- Tender documents may be obtained from and conditions may be obtained from office of the Project Manager, SRHP Skidiri in working hours after depositing cost of 750.00 rupees only.
- Cost of tender Document (Fee in DD) and (TND) shall be in the name of Central Bank (CB) in cash only any Nationalized / Scheduled Bank in favour of Account Holder, Suburban/Urban/ Rural/ Skidiri, Postoffice at Ranchi.
- Tender without Deposit Money shall not be considered.
- No postal transaction for the purchase / submission of Tender Documents shall be entertained.
- The tenderer shall not be responsible for the delay caused by any communication interruption.
- The unopened tender has the right to open, extend the date of sale / submission / opening tender / distribute the works among the bidders without any fee / all tenders without opening any reason allowed.
- For any clarification contact person no. 9411707312 during office hours.

प्रतिष्ठान का मुख्यालय : रांची (सी.टी.डी. नं. 9411707312)
प्र. सं. 330451 Jharkhand Urja Utpadan Nigam Ltd(24-25).D

SRHP Skidiri
Project Manager

आरपीएफ ने दो व्यक्तियों को अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया



नवप्रदेश/झुमरीतिलैया। निरीक्षक प्रभारी कोडरमा के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक, मुर्शिद आलम खान साथ प्रधान आरक्षी,अजय कुमार सिंह तथा महिला आरक्षी,नीतु कुमारी सभी रेसुब पोस्ट कोडरमा के बल-सदस्यों द्वारा गस्ती के दौरान समय करीब 11:00 बजे कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं0 04/05 पर दो व्यक्तियों जिनका नाम व पता क्रमशः (1) विवेक कुमार, उम्र करीब 24 वर्ष, पिता- शैलेश कुमार तथा (2) अश्विनी कुमार, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता-सुधीर कुमार दोनों का पता- लच्छु विगहा, वार्ड सं0 09, थाना-नगरनीसा, जिला, नार्लंदा (बिहार), को दो बैग में कुल 9 अरद अंग्रेजी शराब कि बोतलों के साथ पकड़ा गया। जिसके बाद उक्त दोनों व्यक्तियों से अंग्रेजी शराब के बाबत पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं बेरोजगार हूँ इसलिए इसे बिहार ले जाकर अधिक दामों में बेच कर इसके लाभ कमाता हूँ। अंग्रेजी शराब के बोतल के बाबत न तो कोई कागजात दिखाया और ना ही संतोषप्रद जबाब दिया। जिसके बाद मौके पर ही सहायक उप निरीक्षक, मुर्शिद आलम खान, रेसुब पोस्ट, कोडरमा के द्वारा उपलब्ध गवाहों के समक्ष उपर्युक्त अंग्रेजी शराब की बोतलों को जप्ती सूची बनाते हुए जप्त किया गया तथा पकड़े गये दोनों व्यक्तियों का गिरफ्तारी ज्ञापन बनाते हुए गिरफ्तार किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही वास्ते रेसुब पोस्ट कोडरमा पर लाया गया। जब सभी अंग्रेजी शराब की कुल क्षमता 3525 मिली0 व कुल कीमत 3540 रुपए आका गया। गिरफ्तार व्यक्तियों तथा जप्तशुया शराब को अग्रिम कार्यवाही हेतु उत्पाद विभाग कोडरमा को सुपुर्द कर दिया गया।

करंट की चपेट में आने से पूर्व प्रमुख के पुत्र की मौत



नव प्रदेश/गिरिडीह। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के कोटमा गांव में सरिया के पूर्व प्रमुख के पुत्र की करंट की चपेट में आने से मंगलवार को मौके पर मौत हो गई। मृतक प्रसन्न वर्मा उर्फ राहुल पूर्व प्रमुख रामपति वर्मा का इकलौता बेटा था। जाकारी के अनुसार मृतक राहुल अपने घर के समीप एक बाड़ी में बिजली के पोल से लाईन जोड़ रहा था। लाईन जोड़ने के क्रम में ही वह करंट की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। घटना की जानकारी मिलने पर आजसू नेता अनूप पांडेय सहित कई ग्रामीण भी पूर्व प्रमुख के घर पहुंचे और परिजनों को हिम्मत बढ़ाया।

बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया : शेफाली

नव प्रदेश/हजारीबाग। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बजट पेश किया। आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा की महिला नेता शेफाली गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में विशेष रूप से अन्नदाताओं, महिलाओं की समृद्धि, युवाओं के रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केन्द्रित है। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। शेफाली ने कहा कि यह कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और नई पीढ़ी के सुधार, चुनौतिक समृद्धि एवं सशक्त विकास को समर्पित बजट है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया।

सड़क दुर्घटना में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत

नव प्रदेश/दुमका। जिले के नेशनल हाईवे 133 स्थित सैरैयाहाट थाना क्षेत्र के बाबुडीह गांव के समीप सोमवार की रात सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल शख्स की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मुख्तार अंसारी (50) सड़क पर कर रहा था। इसी दौरान हंसडीहा की ओर से आ रही कार ने उसे सामने से रौंद दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सैरैयाहाट पुलिस ने उसे सीएचसी सैरैयाहाट पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे देवघर रेफर कर दिया। देवघर में मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है जबकि चालक अंधेरे की वजह से भाग निकला।

मूलनिवासी समाज पार्टी ने मांगों को लेकर कोडरमा में दिया धरना

नव प्रदेश/ कोडरमा। मूलनिवासी समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कृष्ण के नेतृत्व में मंगलवार को कोडरमा समाहरणालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया। श्री कृष्ण ने बताया कि कोडरमा एससी एसटी थाना कांड संख्या 3/24 को सूचक गीता देवी पति अशोक तुरी के द्वारा ग्राम पंचायत, ढोढाकोला की मुखिया सीता देवी और जितेन्द्र कुमार सिंह के बहकावे पर एक झूठा और मनगढ़ूंत कहानी बनाकर दर्ज किया गया है। जबकि गीता देवी से किसी भी तरह से कोई विवाद ही नहीं हुआ है। सीता देवी और जितेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा जमीन हड़पने कि नीयत से गीता देवी पति अशोक तुरी से षड़यंत्र रच कर केस दर्ज कराया गया है। मौजा नलवा में दुर्गा यादव, रीतलाल यादव, शंकर यादव, रौशन यादव, विजय यादव, रामदेव यादव, मोहन यादव, जयमर्ति देवी, सुलभा देवी, बसंती देवी वगैरह की जमीन है। दुर्गा यादव ने बताया कि नलवा में खेती करने के लिए ट्रैक्टर से अपना-अपना खेत जोतने के लिए गए थे। सीता देवी और जितेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा गांव के लोगों को बहकाकर अशोाति फैलाकर जमीन हड़पना चाहती है। झूठा और मनगढ़ूंत कहानी बनाकर किए गए केस से बरी करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त कोडरमा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कोडरमा को लिखित आवेदन दिया गया और आवेदन देने के बाद भी ना ही केस से बरी किया गया। दो-तीन बार पुलिस अधीक्षक कोडरमा से और आठ-दस बार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कोडरमा से मिलकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया।

विकसित भारत का यह बजट सर्वस्पर्शी : अन्नपूर्ण

नव प्रदेश संवाददाता

कोडरमा। 23 जुलाई 2024। आज केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2024 का केन्द्रीय बजट पेश किया। केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि विकसित भारत का यह बजट सर्वस्पर्शी, समावेशी एवं 140 करोड़ भारतवासियों के जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने का आर्थिक रोड मैप है। बजट सरकार के 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर फोकस को उजागर करने वाला एक उत्कृष्ट और संतुलित बजट है जो आने वाले वर्षों में भारत के विकास पथ को प्रशस्त करेगा। पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। चुनौतिक समृद्धि एवं सशक्त विकास के पथ पर देश को ले जाने वाले इस बजट में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने,



रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और नई पीढ़ी के सुधार पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। इस ऐतिहासिक बजट में शिक्षा, रोजगार और

कौशल विकास पर खास जोर दिया गया है। यह बजट विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास के नये अवसर प्रदान करेगा। यह भारत की क्षमता, विशेष रूप से इसके युवाओं की क्षमता और गरीबों, महिलाओं और किसानों के लिए समृद्धि की राह सुनिश्चित करता है। बजट में महिलाओं और बालिकाओं पर

बीटीटी का काम है सहिया के साथ बैठक : डा़ सिद्धार्थ सन्याल

नव प्रदेश संवाददाता

सतगावा। प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वित्तीय अनियमितता व घोटाला की जांच को लेकर मंगलवार को क्षेत्रीय उपनिदेशक हजारीबाग डॉ. सिद्धार्थ शन्याल सीएचसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लगभग 4 घंटे तक गहन जांच किया।।जांच में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सत्यनारायण भक्त, लिपिक सह लेखा प्रबंधक अजीत कुमार, बीपीएम मनोज राम एवं बीटीटी दिनेश चौधरी से लिखित बयान लिया।वहीं उन्होंने जांच के बाद मीडिया को बताया कि इस सन्दर्भ में जानकारी लिया गया है। जननी सुरक्षा योजना में जो होना चाहिए था वो नही हुआ। इस मामले को लेकर बीते सोमवार को भी जिला



प्रशासन के द्वारा जाँच किया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि एक साल का है या विगत तीन साल का है ाये देखना होगा। इसके लेकर कुछ कागजात लेकर जा रहे है इससे पता चलेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि योजना में वित्तीय अनियमितता होने की बात कही। वहीं उन्होंने बताया कि इस विषय पर सिविल सर्जन से बात हुई है। हाई कॉपी पर पदाधिकारी को हस्ताक्षर होना चाहिए था जो नहीं

पाया गया।साथ ही उन्होंने कि प्रभारी बैंक एकाउंट का कस्टोडियन होते हैं। प्रथम दृष्ट्या में जो इनको डील किये हैं। सभी पर आरोप बनता है। बी.टी.टी.जो कम्प्युनिटी प्रोसेस का व्यक्ति है वो इसमें कैसे शामिल हुआ ये देखने होगा। क्योंकि बी.टी.टी.व सहिया साथी का कार्य सिर्फ एन.एच.एम.कार्यक्रम को देखना है। लेकिन बी.टी.टी.को वित्तीय कार्य कैसे दिया गया जो संदेह को पैदा करती है।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बीडीओ ने की बैठक



नव प्रदेश संवाददाता

खूटी। तोरपा के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमुद कुमार झा ने मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की चर्चा की। बैठक में बीडीओ ने बताया कि मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संश्लिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इसके तहत 25 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के

लिए सोशल मीडिया के माध्यम से नाम जांचो अभियान का संचालन करने का निर्णय झारखंड निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया है। इसके तहत 25 जुलाई को सभी मतदान केन्द्रों पर वीएलओ मतदाता सूची के प्रारूप के साथ उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने अपील की कि प्रत्येक मतदाता अपने नाम की जांच मतदान केन्द्र पर जाकर प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची से कर लें। मतदाता ऑनलाइन, वोटर हेल्पलाइन एम या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड की वेबसाइट के माध्यम से भी जांच

कर संतुष्ट हो सकते हैं। बीडीओ ने कहा कि नाम जांचने के पश्चात सोशल मीडिया पर इस आशय का पोस्ट नाम जांचो हैश टैग के साथ फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर करें ताकि अन्य लोग भी इसके लिए प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है या कोई अन्य त्रुटि है, तो वे नाम पंजीकरण करने एवं सुधार आदि कें लिए आवेदन समर्पित करें। उन्होंने कहा कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं इस बात ख्याल रखें।

प्लांट नर्सरी का हब बन रहा खूंटी जिला, लोगों को हो रही अच्छी कमाई

नव प्रदेश संवाददाता

खूंटी। आम, जामुन और कटहल जैसे फलों का हब कहे जाने वाले खूंटी जिले में प्लांट नर्सरी भी अब व्यवसाय का रूप लेती जा रही है। अधिक दिन नहीं हुए जब लोगों को किसी प्रकार के फल और फूल के पौधे खरीदने के लिए रांची जाना पड़ता था लेकिन अब खूंटी जिले में प्लांट नर्सरी की भरमार होती जा रही है। जिले के सभी छह प्रखंडों के दर्जनों गांवों में इन दिनों सैकड़ों पौधशालाओं का संचालन किया जा रहा है। हुटार, डांडोली, जिकिलता, मुहू, तोरपा, अड़की सहित कई क्षेत्रों में इन दिनों सैकड़ों नर्सरी संचालित हैं।



जलवायु परिवर्तन विभाग के जरिए विभिन्न गांवों में प्लांट नर्सरी का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ लोग भी अब इसे व्यवसायिक रूप से अपनाने लगे। खूंटी के

ग्रामीण इलाकों में ऐसी कई नर्सरी हैं, जहां विभिन्न तरह के फल और फूलों के पौधों के अलावा विदेशों से मंगाये गये पौधे भी उपलब्ध है। इन पौधशालाओं में सैकड़ों प्रजाति

विशेष ध्यान दिया गया है। इस वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। नाबालिग बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एनपीएस-वात्सल्य योजना शुरू की जा रही है जिसमें नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान किया जाएगा जिसमें नाबालिग के वयस्क होने पर योजना को निर्बाध रूप से सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन किया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर 3% की वार्षिक ब्याज छूट मिलेगी जिसके लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे। इस योजना से हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लाभ मिलेगा। आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतुष्टि कवरेज को अपनाएगी। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। इसमें सबसे अधिक लाभ झारखंड को मिलेगा। बजट में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे की घोषणा की गई है जो झारखंड के की जिलों से होकर गुजरेगा। इससे झारखंड में एक नई औद्योगिक संस्कृति का विकास होगा। एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए इस बजट में आठ नए उपायों का प्रस्ताव किया गया है। सफलतापूर्वक ऋण चुकाने वाले उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर २20 लाख की गई है जिसका छोटे उद्यमियों खासकर महिला उद्यमियों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। पीएम स्वनिधि योजना की सफलता के आधार पर, स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में

बदलाव लाते हुए, सरकार एक योजना लाने जा रही है जिसके तहत चर्चित शहरों में अगले 5 वर्षों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जाएंगे। सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया गया है। इससे सोना- चांदी की कीमतों में कमी आएगी। कैसर मरीजों को राहत देने के लिए तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह हटाने का प्रस्ताव किया गया है। 2024 का आम बजट यह दशातां है कि सरकार विशेषकर किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्व- समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज के इस प्रगतिशील बजट पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा है कि विकसित भारत के लिए यह बजट समावेशी विकास सुनिश्चित करता है, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है।

राजद के कार्यकर्ताओं ने किया पौधारोपण अभियान का शुभारंभ

नव प्रदेश संवाददाता

झुमरीतिलैया। राष्ट्रीय जनता दल, कोडरमा ने एक अनोखे अभियान की शुरुआत मंगलवार से की है। राजद नेता सुभाष प्रसाद यादव के निर्देश पर कोडरमा जिले में वृक्ष लगाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान की शुरुआत राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव और राजद नेता अवधेश प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से विशुनपुर रोड स्थित किशोरी यादव के आवास परिसर में आम वृक्ष लगाकर की। राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव व अवधेश प्रसाद यादव ने कहा कि राजद सुग्रीमो लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय और सामाजिक सौहार्द के नारे को मजबूत करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। पार्टी सुग्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गरीब, गुरवों,पिछड़ा और अकलियतों के हक और हिस्सेदारी के आंदोलन के मजबूत होने के प्रमाण के तौर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम तय किया गया



है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय नारे के कारण ही दलित पिछड़े और अकलियत समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ी। उन्होंने कहा कि जब लोग फलदार वृक्ष को फलता फूलता देखेंगे, तो सहज ही उन्हें सामाजिक न्याय और साम्प्रदायिक सौहार्द के आंदोलन को लालू प्रसाद यादव ने सींचा था, वो आंदोलन के उपजे लोग मान-सम्मान के साथ फल फूल रहे है और जीवनयापन कर रहे है। उन्होंने अपील किया कि साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने वाले लोग आने वाले पीढ़ी के लिए सामाजिक न्याय और सामाजिक सौहार्द के लिए एक पेड़

अवश्य लगाए। राजद नेताओ ने बताया कि राजद कार्यालय सह राजद नेता सुभाष प्रसाद यादव के आवास परिसर में हजारो फलदार वृक्ष का वितरण किया जा रहा है। वहीं राजद का सामाजिक न्याय-सामाजिक सौहार्द की जड़ें को सशक्त बनाये रखने के लिए गांव गांव में वृक्षारोपण अभियान संचालित किया जाएगा। मौके पर राजद युवा जिलाध्यक्ष मनोज रजक, मरकच्चो प्रमुख विजय सिंह, आरंके मिश्रा, अरुण सिंह, घनश्याम तुरी, किशोरी यादव, निरतमान वार्ड पार्षद मीना देवी, विपुल केशरी, प्रमोद यादव, रघुनाथ दास, संजय दास, जैकी यादव समेत कई लोग मौजूद थे।

पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा महाधरना की तैयारी में जुटा



नव प्रदेश संवाददाता

दुमका। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा संताल परगना के केन्द्रीय अध्यक्ष असीम मंडल और प्रधान महासचिव डॉ अमरेन्द्र कुमार यादव ने मोर्चा के प्रमुख साथियों के साथ जर्मुंडी में बैठक की। बैठक की अध्यक्षता समाजसेवी श्रीपति मंडल ने की।

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय अध्यक्ष असीम मंडल ने कहा कि आगामी 30 जुलाई को दुमका समाहरणालय में उपायुक्त के समक्ष आयोजित एकदिवसीय धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में एकजुटता के साथ पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को जिला मुख्यालय में अधिक से संख्या में आने का

अपील किया गया। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को हक दिलाने हेतु मोर्चा अंतिम दम तक आंदोलन करते रहेगी। केन्द्रीय प्रधान महासचिव डॉ अमरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि झारखंड गठन के बाद से ही तत्कालीन सरकार के द्वारा भेदभाव पूर्ण कार्रवाई करते हुए दुमका सहित 7 जिलों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शुन्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जातिगत जगणगना करा कर अखिलंब पिछड़ों को आबादी के अनुरूप आरक्षण देने की राज्य सरकार ने घोषणा तो किया परन्तु सरकार टालमटोल रवैया अपना रही है, जिसे पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने गंभीरता पूर्वक लिया है।

नौकरी छोड़कर शुरू किया नर्सरी का व्यवसाय

तोरपा प्रखंड के डांडोली में नर्सरी का संचालन करने वाले मनोज होरो कहते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर इंजीयनीथिरिंग में डिप्लोमा किया है। उन्हें नौकरी भी मिल गई थी लेकिन उनकी रुचि तो हॉर्टिकल्चर(बागवानी) में थी। उन्होंने अपने गांव आकर नर्सरी के क्षेत्र में हाथ बंटाया। उन्होंने कहा कि लगभग दो साल पहले ही उन्होंने व्यवसाय की शुरुआत की है। फिर भी आमदनी हो ही जाती है। फिलहाल उनकी नर्सरी लगभग तीन एकड़ में फैली हुई और भविष्य में इसके विस्तार की योजना है। मनोज होरो कहते हैं कि पर्यावरण संतुलन के लिए हर किसी को घरों और आसपास के इलाके में पौधारोपण जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी नर्सरी में विभिन्न प्रजाति के आम जैसे आम्रपाली, लंगड़ा, हापुश मालदा, दशहरी आदि के पौधों के अलावा कई तरह के फूल सुवारी स्थायी पौधशाला में पांव से 15 रुपये की दर पर उपलब्ध हैं। खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर स्थित डांडोली में ही वन विभाग के जरिए सुदारी स्थायी पौधशाला का संचालन किया जा रहा है। इस सरकारी नर्सरी में हर दिन विभिन्न तरह के पौधे तैयार किये जाते हैं और काफी कम कीमत पर इसे लोगों को मुहैया कराया जाता है। पौधशाला के कर्मचारी वरुणेंद्र मणिकर कहते हैं कि विभिन्न तरह के पौधों को तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि यहां काफी कम कीमत पर आम, लीची, सागवान, कटहल, अमरुद, महोगनी, जामुन, नीम, कनक चंपा, साल, अर्जुन, बड़हर और अशोक के साथ ही कई अन्य तरह के पौधे उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहां औषधीय और इमारती लकड़ी के पौधे भी उपलब्ध हैं। विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे भी यहां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मलमी आम के पौधे की कीमत सौ रुपये जबकि बीजू आम और अन्य सभी तरह के फलदार और औषधीय पौधे पांव से 15 रुपये में उपलब्ध हैं। मणिकर ने कहा कि ढाई एकड़ के क्षेत्रफल में फैली पौधशाला में हर दिन बीजों और रूटसूट से पौधे तैयार करने की प्रक्रिया जारी रहती है। हर दिन मनुदर काम पर लगे रहते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करें और उसका संरक्षण करें।

के फूलों-फलों के देशी-विदेशी पौधे उपलब्ध हैं। जिले में चल रही पौधशालाएं कई कई लोगों

की आजीविका का आधार बन गई हैं। दिनों दिन इसका कारोबार फलता-फूलता जा रहा

है। कई लोग नर्सरी के माध्यम से हर साल लाखों रुपये की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं।

लक्ष्य के अनुरूप पात्र व्यक्तियों का ससमय बनाये आयुष्मान कार्ड : डीएम



नवप्रदेश संवाददाता

बेतिया। पश्चिम चम्पारण जिलाधिकारी, दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फ़ोर्स की समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुयी। इस बैठक में ऑनलाइन राशन कार्ड से संबंधित प्राप्त आवेदन के निष्पादन की स्थिति, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण, एस0आई0 ओ0/ डोर स्टेप डिलीवरी, खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण, आयुष्मान भारत विशेष अभियान आदि की समीक्षा जिला पदाधिकारी द्वारा की गयी। आयुष्मान भारत विशेष अभियान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आम लोगों की भलाई के लिए यह योजना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गरीबों को लाभ पहुंचाने में सभी जविप्र विक्रेता, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी

सहित अन्य संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत अभिरूचि लें। इसे अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप पात्र व्यक्तियों का आयुष्मान

कार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि इस कार्य में माननीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाय। हर हाल में

लक्ष्य के अनुरूप आयुष्मान कार्ड का निर्माण ससमय पूर्ण किया जाय। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शत-प्रतिशत लाभुकों का आधार

जिले में दस्त रोकथाम अभियान की हुई शुरुआत

आशाकर्मी घर घर जाकर बांटेंगी ओ आर एस का पॉकेट एवं जिक की गोली जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में बनाया गया ओआरएस एवं जिक कॉर्नर

नवप्रदेश संवाददाता

सासाराम। डायरिया से होने वाले शिशु मृत्यु दर को शून्य करने के लिए मंगलवार को सदर अस्पताल स्थित एमसीएच से दस्त रोकथाम अभियान की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अशोक कुमार सिंह ने जिक कॉर्नर एवं ओ आर एस कॉर्नर का फ़ीता काटकर किया और उसके बाद एसीएमओ ने जागरूकता रथ को रवाना किया। सरकार प्रत्येक वर्ष सघन दस्त नियंत्रण अभियान चला कर बच्चों को दस्त से बचाव करती है। वहीं इस वर्ष दस्त रोकथाम अभियान चलाकर दस्त से होने वाली शिशु मृत्यु को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एसीएमओ डॉ अशोक कुमार ने बताया कि बरसात की

शुरुआत होते ही बच्चों में निर्जलीकरण की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है ऐसे में निर्जलीकरण को दूर करने के लिए ओ आर एस का घोल दिया जाता है। उन्होंने बताया कि बच्चों में दस्त होने पर लगातार ओ आर एस के साथ-साथ जिक की गोली दी जाती है। जिक की गोली लगातार 14 दिनों तक बच्चों को देना जरूरी हो जाता है। इसके बावजूद यदि बच्चों में लगातार दस्त हो रहा हो तो उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उन्होंने बताया कि जागरूकता को लेकर जागरूकता रथ भी रवाना किया गया है जो 14 दिनों तक घूम घूम कर दस्त रोकथाम अभियान की जानकारी देगा।

डायरिया के कारण और लक्षण

एसीएमओ ने बताया कि डायरिया होने का मुख्य कारण वायरल या बैक्टीरिया इन्फ़ेक्शन होता है। इसके साथ ही डायरिया के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं जिसमें दूषित पानी, दूषित भोजन का इस्तेमाल, तरल आहार लेना, भोजन न पचना भी डायरिया के कारण हो सकते हैं। यदि इस बीमारी के लक्षण की बात करें तो उसमें पानी जैसा मल होना, अत्यधिक मतली आना, पेट में दर्द और सूजन होना, शरीर में पानी की कमी होना, बार बार बुखार आना, पेट में ऐंठन होना, दस्त(उलटी) होना डायरिया के लक्षण माने जाते हैं।

नियमा विरुद्ध बैंक प्रबंधक का स्थानांतरण किए जाने पर आम जनता ने जताया विरोध

नवप्रदेश/बेतिया। नगर के हजारी मल धर्मशाला में सहायक बैंक प्रबंधक रितेश कुमार का स्थानांतरण बेतिया से रक्सौल किये जाने का मामला जनता को भा नहीं रहा है इस संबंध में बेतिया लोकसभा कांग्रेस के युवा अध्यक्ष विनय यादव, बेतिया सांसद प्रतिनिधि अनिल वर्मा, वाल्मीकिनग सांसद प्रतिनिधि अनिल कुमार, राजद प्रखंड अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, के साथ साथ समाजसेवी पुण्यदेव प्रसाद, शम्भु कुशवाहा, शिवजी मिश्रा, पन्ना देवी, तारा देवी आदि का कहना है कि स्थानांतरण किए गए प्रबंधन एवं बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे तथा सरकारी नियमा कुल काम करते आ रहे थे तथा अभी इनको इस ब्रांच शाखा आए 1 साल कि नहीं हुआ था परन्तु ऐसी हालत में इनका स्थानांतरण किया जाना अपने आप में एक सवाल बना हुआ है ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को स्थानांतरण किया जाना एक चिन्ता का विषय है आम जनता के हित में सरकार एवं बैकिंग प्रणाली से जुड़े आला अधिकारियों से उनको बेतिया ब्रांच ही रखे जाने के साथ साथ बैंक की व्यवस्था जांच की मांग की है वही इस संबंध में बैंक के वरिये अधिकारियों से सम्पर्क नहीं होने के कारण उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।

पंखे में फांसी लगाकर छात्रा ने की आत्महत्या

नवप्रदेश/सासाराम। नगर थाना क्षेत्र के फजलगंज में सोमवार की रात किरायो के कमरे में रह रही छात्रा ने पंखे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका की पहचान गंगा कुमारी 20 साल के रूप में की गई है, जो राजपुर थाना क्षेत्र के तुर्कवलिया गांव के विजेंद्र चौधरी की लड़की थी। मिली जानकारी के अनुसार मृतिका सासाराम में रह कर पढ़ाई करती है। चार दिन पहले ही अपने गांव से लौटी थी। युवती ने आत्महत्या क्यों किया है फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

महापौर की सख्ती पर, आशा नगर में रोड पर जल जमाव का ऑन स्पाॅट समाधान

आदेश के बावजूद महीनों पैमाईस लटके होने से जारी जल जमाव से लोगों को नहीं मिल पा रहा था निजात

सांसत में पड़े लोगों से तीसरी बार शिकायत मिलने पर सख्त होकर दल बल के साथ मौके पर पहुंची महापौर

नवप्रदेश/बेतिया। महापौर गरिमा देवी सिकारिया की सख्ती के बाद नगर निगम के वार्ड 40 में आशा नगर में रोड पर महीनों से जारी जल जमाव की समस्या का



आखिरकार ऑन स्पाॅट समाधान हो गया। सड़क पर नाला का पानी बहने से परेशानी में पड़े

को पुनः मौके पर पहुंचीं। नगर निगम के उपायुक्त गोपाल कुमार, अभियंता सुजय सुमन आदि की उपस्थिति में निगम के अमीन मुन्ना कुमार की पैमाईस के आधार पर सड़क की अतिक्रमित जमीन में महापौर सिकारिया ने तत्काल कच्चा नाला चिरवा कर जल निकासी को शुरू कराया। यहां उल्लेखनीय है कि लोगों की लिखित शिकायत पर महापौर के आदेश के बावजूद महीनों पैमाईस कार्य को नगर निगम प्रशासन द्वारा महीनों से लटकाए होने से जारी जल जमाव से लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा था। महापौर ने बताया कि सड़क की जमीन के दोनों छोरों पर शीघ्र ही पक्के नाले का निर्माण कराया जाएगा।

मुहल्लावासी लोगों से तीसरी बार शिकायत मिलने पर सख्त होकर महापौर दल बल के साथ मंगलवार

सीडिंग तथा ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित किया जाय। एसआईओ एवं डोर स्टेप डिलीवरी कार्य विभागीय दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ससमय संपादित किया जाय। इसके साथ ही शत-प्रतिशत एसआईओ को डिस्पैच कराना सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि संबंधित जविप्र दुकानों की नियमित एवं औचक रूप से गहन जांच करें। जांच के दौरान गड़बड़ी मिलने पर तुरंत वरिये अधिकारियों को सूचित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही लाभुकों को निर्धारित मात्रा में ससमय खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाय। बैठक में उपस्थित जिला प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निर्देश दिया कि जविप्र दुकानदारों को निर्धारित मात्रा में तथा स्वच्छ खाद्यान्न उपलब्ध

करायें। साथ ही खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे। जीएम, एसएफ़सी खाद्यान्न गोदामों की औचक जांच करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा आरटीपीएस कार्डेंटर पर राशन कार्ड के लॉबित आवेदनों को समय सीमा के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्ताव देने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कुमार रविन्द्र, अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर, विनोद कुमार, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेतिया, संजय कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, सुजीत कुमार सहित सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

कार्यकर्ता आभार सम्मेलन सह समीक्षा बैठक आयोजित

नवप्रदेश/खगड़िया। राष्ट्रीय जनता दल खगड़िया द्वारा आयोजित बेलदौर विधानसभा में कार्यकर्ता आभार सम्मेलन सह समीक्षा बैठक पूर्व एमएलसी प्रत्याशी सह राजद जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बेलदौर प्रखंड के एस रज विवाह भवन में सम्पन्न हुई। कार्यकर्ता आभार सम्मेलन सह समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि कोशी स्नातक के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी सह युवा राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नितेश यादव और राजद जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव थे। राजद जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव ने बेलदौर विधानसभा के राजद के सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप लोगों का सबसे पहले में धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में भाग लिये। आप लोग से कहना है कि आप लोग बेलदौर विधानसभा के एक गाँव और घर में जाकर यह बताने का काम करें कि बिहार के युवाओं किसान, मजदूर दलित, शोषित पीड़ित, पिछड़ा वर्ग और अतिपिछड़ा वर्ग के उत्थान लिए गरीबों के मसीहा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही काम करते रहे हैं इसलिए आप लोग राजद को वोट करें क्योंकि नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो कहते हैं वो करते हैं 2020 के चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो दस लाख युवाओं को रोजगार देंगे और महागठबंधन की सरकार में जब वे उपमुख्यमंत्री बने तो महज सत्रह महीने में बिहार के पाँच लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किये और सभी विभागों में दो लाख सेअधिक बहाली प्रक्रिया में थी की साजिश के तहत बीजेपी के लोग महागठबंधन की सरकार को चलने नहीं दिया क्योंकि एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार जो काम सत्रह साल में नहीं कर पायी थी उसे तेजस्वी प्रसाद यादव ने करके दिखा दिया। स्वास्थ्य विभाग में बिहार के सभी अस्पताल में मरीजों के लिए मिशन सिक्स्टी चलाकर साठ दिन के अंदर निशुल्क एम्बुलेंस, जाँच की व्यवस्था, एक्सरे, सिटी स्कैन, आईजीएमएस पटना भी निशुल्क जाँच और दवाई की व्यवस्था किये। पर्यटन विभाग और उद्योग विभाग के माध्यम से बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था किये। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार के एक ही नेता हैं जो दिला सकते हैं वे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ये जो कहते हैं वो करते हैं इसलिए आप लोग 2025 के चुनाव में मेहनत कर तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाईं। युवा राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितेश यादव और कार्यक्रम के संयोजक सह राजद जिला महासचिव चंदन सिंह ने कहा कि बिहार राज्य में जिस प्रकार अपराध की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं और अपराधियों के मन में पुलिस प्रशासन का भय समाप्त हो गया है। पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल कायम है क्योंकि शासन व्यवस्था बंधे हुए हाथों में है रिटायर अधिकारी साशन चला रहे हैं। बिहार में अभी महाजंगल राज्य है प्रतिदिन लूट ,अपहरण हत्या आम हो गई है। खगड़िया में भी कई अपराधिक घटनाएं हो रही है। बिहार को अब युवा ऊर्जावान और जो कबे वह करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए बिहार में मात्र एक ही नेता हैं वे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव इसलिए बिहार के लोगों ने तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है।

स्वास्थ्य कर्मचारीयो ने किया पीएचसी के गेट पर 10 सूत्री मांगो को लेकर अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार

पेन्स अटेंडेंस का विरोध किया है विदित हो कि सरकार के दोहरी नीति का विरोध करते हुए महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए सभी संविदा जीएनएम एएनएम अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हैं। उक्त संबंधों में सभी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा 12 जुलाई को अपनी मांगों को लेकर पटना गर्दनीबाग से कार्यपालक निदेशक को अपना मांग पत्र भी सौंपा था अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर नारेबाजी करते हुए एनएचएम के समस्त कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर डटे रहेंगे। हम महिला कर्मी को सुदुर गाँवों तक जानी पड़ती है।

जहां इंटरनेट की सुविधा और स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि मौलभूत सुविधा भी नहीं मिलती है। वैसे में हम शाम 5:00 बजे तक ड्यूटी कैसे कर पाएंगे हम सब की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, इन सभी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी सीएचओ हारून राशीद, सीएचओ जितेंद्र कुमार, सीएचओ दानवीर कुमार, सीएचओ राजेंद्र कुमार, सीएचओ दिलराज सिंह, स्टाफ नर्स बिजेंद्र कुमार, एएनएम रेखा कुमारी, एएनएम सुभावती गुप्ता, एएनएम पूजा कुमारी, एएनएम सीमा कुमारी के साथ दर्जनों की संख्या में एएनएम आदि स्वास्थ्य कर्मियों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में बाढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।

सुरुचि ने पहले प्रयास में ही पास किया सीएस फाउंडेशन की परीक्षा

नवप्रदेश/दलसिंहसराय। शहर के मौलवीचक नवादा निवासी व्यवसायी उमाशंकर साह एवं गुहणीपुा देवी की सुपुत्री सुरुचि कुमारी ने भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित कम्पनी सेक्रेटरी एक्सच्यूटिव एंटेर्स टेस्ट (CSEET) पास करने का गौरव हासिल किया है। इस प्रकार से सुरुचि ने सीएस बनने की पहली पात्रता हासिल कर लिया है। आरम्भ से ही पढ़ने में मेधावी रही छात्रा सुरुचि ने इसी वर्ष 2024 की परीक्षा में 86.6% अंकों के साथ इंटरमीडिएट कॉमर्स की परीक्षा उत्तीर्ण किया। कम समय में ही सुरुचि ने कड़ी मेहनत एवं लगन से अपना लक्ष्य पूर्ण करने की पहली सीढ़ी पहले अटेम्ट में ही हासिल कर लिया। अपनी सफलता को श्रेय सुरुचि ने अपने मार्गदर्शक उत्तम जायसवाल, तनिषा गुप्ता, गुरुदेव पटेल, सुनील कुमार के अलावे अपने अभिभावकों को दिया है।

आम आदमी के दिल पर खंजर है ये बजट : आलोक

नवप्रदेश/उज्जयिनापुर। उज्जयिनापुर विधायक आलोक कुमार मेहता ने आज केन्द्र सरकार द्वारा पेश वित्त बजट बिहार के साथ धोखा है। बिहार के लोगों से इस वर्ष वोट लेकर उन्हें अंगुठा दिखा दिया गया है। कई वर्षों का बजट बकाया अपनी कुर्सी बवाने के लिए उपयोग किया जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन की पाठियों के साथ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू ने बिहार विधान मंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। इस बजट में बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने, बिहार का सीडी रेश्यो बढ़ाने, कृषि ऋण माफ करने और नौजवानों को रोजगार या सरकारी नौकरी देने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। देश पैमाने पर विकास के इन्वेक्स में सबसे नीचे पंदान पर खड़ा बिहार, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात जोह रहा था, जो आज टग्रा सा महसूस कर रहा है।

विष्णुपद धाम गया बोधगया कॉरिडोर को मिली केंद्र की मंजूरी : डॉक्टर प्रेम कुमार

मदन कुमार/नवप्रदेश/गया। बिहार भाजपा के वरीय नेता और बिहार सरकार के सहकारिता सह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, एवं

राष्ट्रीय अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी को बिहार की जनता की ओर से बधाई दी। डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि 19 जून 2024 को बोधगया एयरपोर्ट पर मोदी जी के नवादा जाने के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने विष्णुपद नगरी व गया बोधगया को विश्व स्तरीय कॉरिडोर निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आवेदन दे आग्रह किया था,जो आज बजट के रूप में सफलभीत हुआ। इस घोषणा के बाद गया जी जनता खुशी की लहर दौड़ गया। गया की जनता की ओर से, बिहार वासियों की ओर से और मैं अपनी ओर से भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी को हार्दिक बधाई एवं अभार। आपने ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया जी के लिए विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद धाम गया बोधगया कॉरिडोर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की हम सब बिहारवासी इस उपकार के लिए आप सबों का सदा ऋणी रहेंगे।

बिहार के राज्यपाल व मुख्यमंत्री के साथ महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल की शिष्टाचार भेंट

नवप्रदेश/हाजीपुर। बिहार के राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आलंकर एवं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने पटना में शिष्टाचार मुलाकात की एवं बिहार राज्य में यात्री सुविधा और रेल विकास से जुड़े पूर्व मध्य रेल की विभिन्न योजनाओं की प्रगति से उन्हें अवगत कराया। महाप्रबंधक ने रेलवे के क्रिया-कलाप, यात्री सुविधा में और सुधार के उपायों तथा रेल विकास आदि से जुड़े विषयों पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया। महाप्रबंधक ने बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री स्मरट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा तथा पुलिस महानिदेशक राजविरेंद्र सिंह भट्टी से भी शिष्टाचार मुलाकात की।

बजट पर प्रधानमंत्री ने बिहार में विकास कार्य के लिए दी बड़ी सीगात : अर्थशास्त्री डॉ. मनीष

नवप्रदेश/विक्रमगंज। मंगलवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत 58900 करोड़ रुपये का सीगात मिलते ही अब बिहार में विकास कार्य के चार-चांद लगने की उम्मीद जाग गई है। इनमें से 26 हजार करोड़ रुपये का फंड बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछाने के लिए, राज्य में तीन एक्सप्रेसवे बनाने के लिए बजट पेश राशि खर्च होगी। वहीं बजट पारित होने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री अर्थशास्त्री डॉ. मनीष रंजन ने बताया कि इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11500 करोड़ सहित पावर प्लांट के लिए 21400 करोड़ रुपये जारी की गई है। जो बिहार के जनहित में इस बजट को ऐतिहासिक बजट माना जा रहा। इस बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पारित बजट देश के जनहित में भी सबका साथ सबका विकास तहत मजबूती प्रदान कर रही है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, रॉडियम, औद्योगिक हब, महाबोधि कॉरिडोर, नालंदा और राजगीर में पर्यटन सुविधा के विकास की घोषणाएं भी कीं। आम बजट को लेकर अर्थशास्त्री डॉ. मनीष रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के लिए विकास कार्य के लिए विशेष पैकेज देना देश के आजादी काल के बाद बिहार के लिए यह ऐतिहासिक पल है। केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए एक से एक योजनाओं के लिए जो राशि स्वीकृत की है। उससे बिहार में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन बिहार के विरोधी दलों को विकास कार्य की सीगात भरी पेश बजट पच नहीं रही है। वहीं बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार के चौदमुखी विकास के सपने सह होने लगे है।

विक्रमगंज मलियाबाग मुख्य पथ के कल्याणी मोड़ पर चेकिंग के दौरान ट्रक से जुमार्ना वसूला गया

नवप्रदेश/सूर्यपुर। थाना पुलिस ने क्षेत्र के बिक्रमगंज-मलियाबाग मुख्य पथ पर कल्याणी मोड़ के समीप जाँच के क्रम में एक ट्रक से जरूरी कागजात के अभाव में साढ़े बार हजार रुपए जुमार्ना वसूला अपर थानाध्यक्ष प्रिया कुमारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के कल्याणी मोड़ के पास सोमवार की संख्या वाहन चेकिंग अभियान थाने के एसआई बसंत कुमार द्वारा चलाया जा रहा था। गुप्त सूचना के अधार पर बिना नंबर प्लेट के सीमेंट लॉड एक ट्रक को गहरता से जांच किया गया। जांच में अंदर भी कुछ आपति जनक सामग्री नहीं पाया गया। परन्तु उक्त ट्रक का इश्योरेंस फेल था। जबकि जाँच के क्रम में नंबर प्लेट पत्र हुआ। जिसका नंबर है पढ 677/2489 ऑफि था। जो जांच में सहो पाया गया। परन्तु इच्छित मुक्ति होने के करण साढ़े चार हजार रुपए जुमार्ना वसूल कर ट्रक को छोड़ दिया गया।

सावन की प्रथम मंगलवारी को क्षेत्र के सभी हनुमानजी के मंदिरों में भक्तों ने की पूजा अर्चना

नवप्रदेश/सूर्यपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित हनुमानजी के मंदिर सहित क्षेत्र के विभिन्न हनुमान मंदिरों में सावन के प्रथम मंगलवारी को भक्तों ने धूमधाम से पूजा-अर्चना किया। वहीं हनुमान मंदिर बंगला चौक सूर्यपुर, सूर्यपुरा महावीर स्थान, बारून सहित विभिन्न गाँवों में हनुमान भक्तों ने धूमधाम से पूजा अर्चना किया। पंडित शंभू नाथ पांडेय एवं उत्तम चौबे ने बताया कि सावन में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत माता-पार्वती को समर्पित माना जाता है। वहीं मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलने के साथ-साथ मनोकामनाएं भी पूरी होती है।

सीएचसी में स्टॉप डायरिया कार्यक्रम का शुभारंभ

नवप्रदेश/काराकाट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काराकाट (गोड़ारी) में मंगलवार को स्टॉप डायरिया कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ राहुल कुमार सिंह व प्रमारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार व यूनिसेफ बीएमसी प्रमित कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। स्टॉप डायरिया के बारे में जानकारी देते हुये बताया गया कि बरसात के मौसम में स्याॅट डायरिया बच्चों में फैलने की संभावना रहती है। बच्चों में दस्त के रोकथाम के लिए स्टॉप डायरिया कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रखंड क्षेत्र के सभी गांव व शहरी क्षेत्र के लोगो को जागरूक करते हुए आशा के द्वारा घर घर जाकर दो वर्ष से पांच वर्ष आयु के बच्चो को ओआरएस एवं जिक टेबलट वितरण किया जाएगा। स्टॉप डायरिया कैम्पेन 2024 जो 23 जुलाई से 27 सितंबर तक चलेगा। साफ-सफाई पर भी लोगो को जागरूक किया जाएगा। बच्चों में दस्त की समस्या से निपटने और शून्य बाल मृत्यु दर के लिए प्रयास करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने अपने लंबे समय से चल रहे गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़े को स्टॉप डायरिया अभियान के रूप में संचालित कर रही है। यह अभियान डायरिया की रोकथाम, सुरक्षा और उपचार रणनीति को बढ़ाने और ओरल रिहाइडेशन संकल्पित और जिक के उपयोग को बढ़ाने के केन्द्रित है। अभियान का 2024 का नारा, डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान, रोकथाम, स्वच्छता और उचित उपचार का विशेष महत्व है। बीडीओ राहुल कुमार सिंह ने कहा की प्रखंड के सभी पीडीएस दुकानों पर आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की कार्य शुरू किया गया है. प्रखंड क्षेत्र के सभी लाभार्थी 1 अगस्त 2024 तक अलाई कर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते है। मौके पर बीसीएम पूरम मेहता, डाटा ऑपरेटर नागेश्वर तिवारी, एएनएम, डॉक्टर, आशा, जीविका सहित स्वास्थ्य कर्मी शामिल थे।

जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज एवं ज्ञान ज्योति विद्यालय ने रचा इतिहास



नवप्रदेश/आरा। स्थानीय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा दुर्घ वृक्षारोपण समारोह जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज में किया गया है। मुख्य अतिथि स्वरूप पवारे गया शिक्षक क्षेत्र के पार्षद जीवन कुमार ने विद्यालय एवं कॉलेज के छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि बड़ती जलवायु परिवर्तन को देखते हुए प्रकृति की रक्षा करना अति आवश्यक है। जीवन ने हाल ही में कोरोना संक्रमण काल में ऑक्सीजन के महत्व की याद दिलाते हुए कहा कि जीवन चलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। संक्रमण काल में हमने देखा है कि ऑक्सीजन की किन्तनी आवश्यकता होती है। प्रकृति ने हमें मुफ्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराया है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपने और पूरे विश्व के कल्याण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगायें। उन्होंने बताया कि वर्तमान जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से देशव्यापी हाइक पेड़ मों के नाम मुहिम चल रही है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक भारतवासी से एक पेड़ लगाने की अपील की गई है। आज ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय एवं जिनवाणी मैनेजमेंट कॉलेज द्वारा 500 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना प्रकृति की रक्षा में श्रेयस्कर भागीदारी है।

■ बजट प्रतिक्रिया

विपरीत परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत : धरमलाल

बिलासपुर/नवप्रदेश। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरम लाल कौशिक ने कहा है कि केंद्र के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान, युवा पर बजट में फोकस किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया गया है। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है। जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। उन्होंने कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं का पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन से रोजगार मिलेगा, उनका कौशल बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए मकानों का ऐलान ग्रामीण विकास के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा।

देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट : अमर

बिलासपुर/नवप्रदेश। पूर्व वित्त मंत्री एवं विधायक अमर अग्रवाल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में सर्वांगीण, सर्वव्यापी तथा सर्व-समावेशी विकास के साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना की गई है।बजट में चार वर्ग गरीब, महिला, युवा और किसान का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा इस बजट में विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर फोकस किया गया है। कौशल और रोजगार सृजन की घोषणाएं ऐतिहासिक हैं। 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को सीधा लाभ होगा। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए उत्पादकता और अनुकूलनीयता 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर नए घर बनाये जाएंगे।मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है।बजट में एमएसएमई के लिए वित्तीय पैकेज का ऐलान किया गया है।

समुचित विकास का रखा ख्याल : सक्नी

बिलासपुर/नवप्रदेश। यह बजट विकसित भारत की संकल्पना के ऊर्जा से ओतप्रोत है। इसमें एक तरफ ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में समुचित विकास हो इस बात का ख्याल रखा गया है। यह बजट देश के युवाओं के शिक्षा और रोजगार के नए अवसर सृजित करने वाला बजट है।

महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने वाला बजट : हर्षिता

बिलासपुर/नवप्रदेश। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हर्षिता पांडेय ने आम बजट का स्वागत करते हुए इसे महिलाओं के सम्मान में वृद्धि करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल की है, जो सरहनीय है। इसके अंतर्गत उद्योगों के साथ मिलकर महिला हॉस्टल और बाल गृहों की स्थापना में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। हर्षिता पांडेय ने कहा कि एमएसएमई गारंटी फंड के अंतर्गत लोन मिलने से महिलाओं में आर्थिक स्वावलम्बन बढ़ेगा साथ ही उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी में महिलाओं को छूट देने का भी स्वागत किया।

जनकल्याणकारी बजट : चौहान

बिलासपुर/नवप्रदेश। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने मोदी कार्यकाल के प्रस्तुत तीसरे बजट को गांव, गरीब और जनहित का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार कौशल प्रशिक्षण के साथ युवाओं को लाभ मिलेगा। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को भी मजबूत करने बजट में स्थान दिया गया है। मोदी सरकार की यह बजट सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। श्री चौहान ने कहा कि मैं खुद कृषक पृष्ठभूमि से हूं, इसलिए मोदी सरकार के बजट को एक कृषक के नजर से देख रहा हूं, जो कृषि कल्याणकारी बजट है।

कृषि विकास पर जोर : विक्रम सिंह

बिलासपुर/नवप्रदेश। जनपद पंचायत बिल्हा के उपाध्यक्ष युवा भाजपा नेता विक्रम सिंह ठाकुर मोदी सरकार के प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा जनहित को ध्यान में रखकर हमेशा बजट प्रस्तुत की है। इस बजट में भी सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। चाहे युवा ही या किसान। बजट में कृषि सिंचाई के लिए करोड़ों साढ़े 11 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को भी अगले पांच साल तक जारी रखा जाए।

केन्द्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर का हिस्सा 1.2 प्रतिशत बढ़ा, 42,277.74 करोड़ रुपये आवंटित

जम्मू। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केन्द्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर को 42,277.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए 41,751.44 करोड़ रुपये से 1.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि है। मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए बजट में जम्मू-कश्मीर में संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता के रूप में 40,619.3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

बजट में कहा गया है कि इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत 7,900 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए व्यय को पूरा करने के लिए जम्मू और कश्मीर को 279 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बजट में केंद्र शासित प्रदेश को 624 मेगावाट की किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (एचईपी) के लिए इकट्टी योगदान के लिए 130 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं,



जबकि 800 मेगावाट की रतले एचईपी के लिए इकट्टी के लिए 476.44 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसके अलावा झेलम और तवी बाढ़ पुनर्प्राप्ति परियोजना (जेटीएफआरपी) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है। दस्तावेज में कहा गया है कि केंद्र ने 540 मेगावाट केडब्ल्यूआर एचईपी के लिए इकट्टी योगदान के लिए अनुदान के रूप में जम्मू और

कश्मीर को 171.23 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संसाधन-अंतर निधि को पूरा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के पूंजीगत व्यय के लिए समर्थन के रूप में 101.77 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 42,277.74 करोड़ रुपये के कुल बजट के अलावा केंद्र ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को 9,789.42 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं।

अमलाई का रेलवे गुड्स शेड फिर होगा शुरू

- ◆ कोर्ट ने रेलवे के पक्ष में सुनाया फैसला
- ◆ स्थानीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को मिलेगी राहत

बिलासपुर/नवप्रदेश। अमलाई रेलवे गुड्स शेड मामले में 18 जुलाई को महत्वपूर्ण फैसला आया है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (प्रधान खंड पीठ) ने रेलवे के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए गुड्स शेड को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीओ लेने के बाद फिर से चालू करने की अनुमति दी है। इस फैसले के बाद, रेलवे प्रशासन ने तुरंत अमलाई गुड्स शेड को फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ज्ञात हो कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा रेल कोल

यातायात के कारण प्रदूषण उत्पन्न होने एवं स्थानीय रहवासियों की प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रही परेशानियों को देखते हुये उच्च न्यायालय में याचिका दाख की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा 25 अप्रैल 2024 से अमलाई रेलवे गुड्स शेड पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण पाण्डेय के मार्गदर्शन व वरि.मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अनुराग कुमार सिंह के निर्देशन में रेलवे प्रशासन द्वारा इस याचिका को चुनौती देते हुये उच्च न्यायालय द्वारा चाहे गए सभी मुद्दों पर जानकारी प्रदान की गई साथ ही मजबूती से अपने पक्ष को रखा गया। परिणाम स्वरूप बहुत ही अल्प समय लगेभा 03 माह के अंदर ही उच्च न्यायालय ने रेलवे के दलीलों से संतुष्ट होकर रेलवे के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए अमलाई गुड्स शेड को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मान्य शर्तों के साथ फिर से चालू करने की अनुमति दी गई है। वरि.मंडल

वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया, हम उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और इसे जनता के हित में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। इससे न केवल माल परिवहन में तेजी आएगी, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। गुड्स शेड के फिर से चालू होने से स्थानीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को भारी राहत मिलेगी, जो अपने माल के तेज और सुगम परिवहन के लिए इस शेड पर निर्भर रहते थे। इस आदेश से कोयले के अलावा विद्युत, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, स्टील, कच्चा तेल एवं सीमेंट के उत्पादन एवं वितरण में अत्यधिक लाभ होने की संभावना है। इस प्रकार पावर, सुरक्षा जैसे आधारभूत तत्वों के न केवल संरक्षण बल्कि उत्पादन को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह कदम रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

सावन: 72 साल बाद महायोग, सोमवार से शुरुआत और समापन



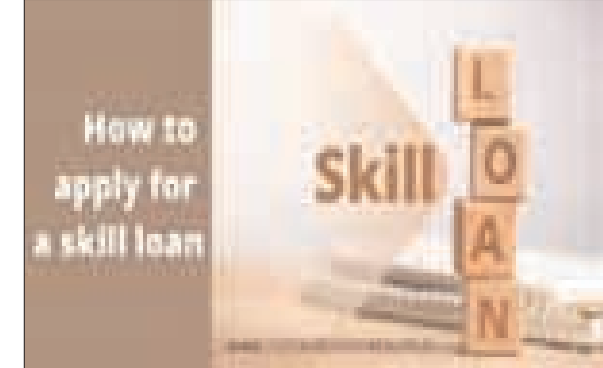
पंडित आकाश जी महाराज

भगवान शिव के प्रिय मास सावन का इंतजार कर रहे भक्तों के लिए इस बार दुर्लभ और महायोग बन रहा है। 72 साल बाद सावन की शुरुआत और समापन सोमवार से होगा, वहीं इस बार पांच सोमवार पड़ रहे हैं। ऐसे योग में भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करने वाले भक्तों पर कृपा बरसेगी। सावन की शुरुआत 22 जुलाई से हो चुकी है और समापन 19 अगस्त को होगा। हिंदू कैलेंडर के पांचवें मास सावन का विशेष महत्व है। भक्त भगवान शिव का पूजन-अर्चन, शिवालयों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और अभिषेक आदि अनुष्ठान करवाते हैं। बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का रेला उमड़ता है।

कावड़ यात्राएं निकलती हैं। ऐसे में सावन में पांच सोमवार पड़ने से भक्तों को भगवान शिव की आराधना के लिए एक दिन और मिलेगा। 29 दिनों का सावन इस बार सावन मास 29 दिनों का ही है। इन्हें 29 दिनों में पांच सोमवार का दुर्लभ योग बनेगा। पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा पांच अगस्त, चौथा 12 अगस्त, पांचवां और अंतिम सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। वहीं, सावन नक्षत्र और प्रीति योग बन रहा है। हिंदू धर्म में सावन की शुरुआत और समापन सोमवार से होना दुर्लभ संयोग है। ऐसा 72 साल बाद हो रहा है। सावन मास का महात्म्य सुनने योग्य होता है। इसके महत्व के श्रवण मात्र से तमाम सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा का भी विशेष महत्व होता है। पिछले साल दो माह का था

सावन पिछले बार सावन में आठ सोमवार पड़े थे। कारण, तीन साल पर पड़ने वाले अधिमास से एक माह बढ़ गया था। सावन दो माह का था और आठ सोमवार पड़े थे। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं से भगवान शिव की आराधना एवं अभिषेक करना चाहिये। जल से अभिषेक : वृष्टि के लिए जल से रुद्राभिषेक करना चाहिये। कुशा जल से अभिषेक : रोग व दुःख से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुशा जल से अभिषेक करें। दही से अभिषेक : पशु, भवन तथा सावन में अग्रपुन तीन मंगलवार पड़ते हैं। इस दिन श्रद्धालु मां मंगला गौरी का व्रत रखते हैं। इस बार मंगला गौरी व्रत चार पड़ रहे हैं। पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई, दूसरा 30 जुलाई, तीसरा छठ अगस्त, चौथा 13 अगस्त को पड़ रहा है। काशी में मां मंगला गौरी के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ होती है। जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही होती है, यह व्रत रखकर मां की पूजा करती हैं और मां को प्रिय हल्दी की माला चढ़ाती हैं।

तीर्थ जल से अभिषेक : अगर मनुष्य भगवान शिव का अभिषेक तीर्थों के जल से अभिषेक करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इत्र मिले जल से अभिषेक : अगर मनुष्य भगवान शिव का अभिषेक इत्र मिले जल से करता है तो उसके सारे रोग नष्ट होते हैं।
दूध से अभिषेक: पुत्र प्राप्ति, प्रमेह रोग की शांति और मनोकामनाएं पूर्ति के लिए दूध से अभिषेक करें करें।
दूध-शर्करा युक्त: दुध और शक्कर को मिलाकर अभिषेक करने से सर्बुद्धि की प्राप्ति होती है।
घी से अभिषेक : वंश विस्तार के लिए घी से अभिषेक करें।
सरसों के तेल से अभिषेक : रोग तथा शत्रुओं के नाश के लिए सरसों के तेल से अभिषेक करें।
शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक : पाप क्षय करने के लिए शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक होता है।
शादी में देरी पर मंगला गौरी व्रत के इस बार चार दिन
सावन में अग्रपुन तीन मंगलवार पड़ते हैं। इस दिन श्रद्धालु मां मंगला गौरी का व्रत रखते हैं। इस बार मंगला गौरी व्रत चार पड़ रहे हैं। पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई, दूसरा 30 जुलाई, तीसरा छठ अगस्त, चौथा 13 अगस्त को पड़ रहा है। काशी में मां मंगला गौरी के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ होती है। जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही होती है, यह व्रत रखकर मां की पूजा करती हैं और मां को प्रिय हल्दी की माला चढ़ाती हैं।



पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और डिजाइन तैयार किया जाएगा और नई उभरती जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस योजना के तहत अगले पांच साल में प्रतिवर्ष 20 लाख युवाओं को आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण

दिलाया जाएगा। इसके साथ ही 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कोशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस उपाय से प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलेगी।

मनरेगा से बने कुएं से खेती में मिल रही सुविधा दो फसल लेने से बढ़ी आय, संवरी जिंदगी



बिलासपुर/नवप्रदेश। मनरेगा योजना से जिले के ग्रामीणों की जिंदगी संवर रही है रही है। मनरेगा के तहत कराए जा रहे कार्यों से ना केवल उन्हें रोजगार मिल रहा है अपितु इन कार्यों से उन्हें आजीविका का साधन भी मिल गया है। शासकीय योजनाओं से ग्रामीणों को समय-समय पर अवगत कराया जा रहा है जिसका फायदा उठा कर उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। जिले से लगभग 60 कि.मी. दूर मस्तुरी ब्लॉक के ग्राम कुकुर्दीकला की निवासी कृष्णा बाई को भी मनरेगा के तहत लाभ मिला। हितग्राही कृष्णा बाई के पास सिंचाई का साधन नहीं होने से खेती करने में बड़ी परेशानी होती थी। उन्होंने बताया की उनके पास लगभग 2 एकड़ खेत है लेकिन सिंचाई साधन न होने से उनको खेती करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हितग्राही को शासन द्वारा मनरेगा के तहत दिए जाने वाले योजना की जानकारी मिली जिससे उन्होंने कृप निर्माण कार्य की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया। कृप निर्माण का काम मनरेगा के तहत पंजीकृत श्रमिकों के सहयोग से 512 दिन

मानव दिवस सृजित कर पूर्ण कराया गया। इस कार्य में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार का अवसर मिला जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और आमदनी भी मिली। कुंआ बन जाने से हितग्राही को मनरेगा के तहत रोजगार मिला। पानी की पर्याप्त मात्रा मिलने से उनको खेती करने में अब कोई परेशानी नहीं होती है। खेतों में अब सिंचाई के पर्याप्त साधन होने से फसल की पैदावार बढ़ी। अब हितग्राही कृष्णा बाई खरीफ और रबी दोनों फसलों का उत्पादन अपने खेतों में करती है। हितग्राही को अब साल में 60-70 हजार रुपए का मुनाफा हो रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। अब हितग्राही का परिवार सुखद जीवन जी रहा है और अधिक फसल उत्पादन से अपने आस-पास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। श्रीमती कृष्णा बाई ने सपरिवार शासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके इतने बड़े आर्थिक संकट में सरकार ने उन्हें सहारा दिया। अब वे शासन की योजनाओं की जानकारी अपने गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों को भी दे रही हैं।

इतिहास के पन्नों में 24 जुलाई: शह और मात के खेल में एस विजयालक्ष्मी का जवाब नहीं



देश-दुनिया के इतिहास में 24 जुलाई की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। यह तारीख भारतीय शतरंज खिलाड़ी एस विजयालक्ष्मी के जीवन के लिए खास है। शह और मात के इस खेल में अपने धैर्य से प्रतिद्वंद्वी को गलती करने पर मजबूर करने वाली एस विजयालक्ष्मी ने वर्ष 2000 में

24 जुलाई को ही देश की पहली महिला ग्रैंडमास्टर होने का गौरव हासिल किया। 25 मार्च 1979 को जन्मी विजयालक्ष्मी ने कम उम्र से ही शतरंज के दुर्नामेट जीतने शुरू कर दिए थे। राष्ट्रीय खिताब के अलावा वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने फन का लोहा मनवाने में कामयाब रहीं। साल 1995 एस विजयालक्ष्मी के लिए कुछ बड़ा लाने रहा। इस साल उन्होंने इंटरनेशनल विमेन मास्टर टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद उनकी ख्याति विदेश में होने लगी। 1998 में विजयालक्ष्मी ने एनिबल ओपन में रूसी ग्रैंड मास्टर मिखाइल कोबालिया को हराकर सनसनी मचाई। अब तक वह चार बार नेशनल चैंपियन बन चुकी थीं।

विजयालक्ष्मी को चेस खेलने की प्रेरणा उनके पिता से मिली। उन्हीं के साथ खेल-खेल में विजयालक्ष्मी ने चेस खेलना सीखा। चेस में नाम कमाने के बाद विजयालक्ष्मी ने चेस ग्रैंडमास्टर श्रीराम झा से शादी की। उनकी बहनें सुब्बारामन मीनाक्षी और एस भानुप्रिया भी शतरंज की बेहतरीन खिलाड़ी हैं।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र
1758= अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन उत्तरी अमेरिका की पहली असेंबली वर्जीनिया हाउस ऑफ बर्जैसेज में शामिल हुए।
1793= फ्रांस ने कॉपीराइट कानून बनाया।
1830= चिली में दास प्रथा समाप्त।
1911= हैरम बेहन ने माया सभ्यता के लुप्त शहर माचुपिचु की खोज की।
1935= ब्रिटेन में पहला बर्धाई टेलीग्राफ भेजा गया।
1938= इंस्टेट कॉफी की खोज हुई।
1969= अपोलो-11 सफलता पूर्वक प्रशांत महासागर में उतरा।
1989= भारत में लोकसभा में 73 विपक्षी सदस्यों ने बोफोर्स तोप के मुद्दे पर सदन से इस्तीफा दे दिया।
1999= ब्रिटेन के लिबरलुल में प्रथम सावर्भौमिक महिला धर्मसभा का आयोजन।
1999=अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया का सफल प्रक्षेपण।
2000=एस. विजयलक्ष्मी शतरंज की

पहली महिला ग्रैंडमास्टर बनीं।
2002= यूरोपियन यूनियन ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष में 3.20 करोड़ यूरो अतिरिक्त देने का निर्णय लिया।
2004= इटली ने भारतीय पर्यटकों के लिए सात वीजा कॉल सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया।
2005= कोरियाई क्षेत्र को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिए उत्तर और कोरिया के बीच आम सहमति।
2006= प्यूर्तो रिको की जुलेखा रिवेरा मेंडोजा गिस यूनिवर्स चुनी गईं।
2008= फ्रांस के ट्विंकस्टिन परमाणु संयंत्र में रिसाव से लगभग 100 व्यक्ति प्रभावित।
जन्म
1853= ज्योतिषशास्त्र के मराठी

विद्वान शंकर बाल कृष्ण दीक्षित।
1911= भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पन्नालाल घोष।
1928= भाजपा नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल।
1937= प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता मनोज कुमार।
1945= निप्रो कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी।
निधन
1980= हिन्दी और बांग्ला फिल्म अभिनेता उत्तम कुमार।
2017= इसरो के पूर्व अध्यक्ष उडुपी रामचन्द्र राव।
2020= भारतीय नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर अमला शर्मा।

मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देकर सरकार ने उनके सपनों को नया विस्तार दिया: अमित शाह



नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि आम बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देकर उनके सपनों को नया विस्तार दिया है। केंद्रीय मंत्री शाह ने बजट का स्वागत करते हुए एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट कर कहा कि बजट 2024-25 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का देशवासियों की आशा, आकांक्षा व विश्वास पूर्ति के संकल्प का प्रतिबिम्ब है। यह बजट युवाओं व महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ किसानों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाकर विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा देकर देश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाई देने की प्रधानमंत्री मोदी

की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, इस बजट में टैक्स नियमों का भी सरलीकरण किया गया है, जिससे करदाताओं को बहुत आसानी होगी। शाह ने कहा कि टैक्स में छूट हो या उसके नियमों को आसान करना हो, 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास देना हो या कैंसर के मरीजों को दवाओं में राहत देने का निर्णय हो; यह बजट मध्यम वर्ग के जीवन को और भी आसान बनाने वाला है। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण हमेशा से मोदी सरकार की योजनाओं व नीतियों के केंद्र में रहा है। आज बजट में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की घोषणा कृषि क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होने वाली है। शाह ने कहा कि बजट में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सर्टिफाई करने, 10 हजार बायो-इनपुट सेंटरों की स्थापना,

चुनाव के समय की बड़ी-बड़ी बातें कहाँ गईं: ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 के केंद्रीय बजट पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि इस बजट में बंगाल को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा, जिसने उत्तर बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान बड़े-बड़े वादे किए थे लेकिन बजट में उन वादों को भूल गई।

बंगाल के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं

ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि केंद्रीय बजट में बंगाल को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं लेकिन बंगाल का नाम तक नहीं लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्ताव पढ़ते समय 'पूर्वोदया योजना' का जिक्र किया, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात की गई थी। इसके बाद अमृतसर-कोलकाता वाणिज्यिक गलियारे का

भी उल्लेख किया गया लेकिन पूरे बजट में बंगाल के लिए कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया। ममता ने उत्तर बंगाल के मुद्दे पर भी जोर देते हुए कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने बड़े-बड़े वादे किए थे लेकिन अब दाजिलिंग, कालिम्पोंग, कर्सियांग को भूल गई है। उन्होंने उत्तर बंगाल के लोगों से अपील की कि वे इस बजट को याद रखें और भाजपा के वादों की हकीकत को पहचानें।

बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले विशेष लाभ

ममता ने यह भी कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को इस बजट में अधिक लाभ मिलने की संभावना पहले से थी, क्योंकि इन राज्यों की पार्टियों ने केंद्र में भाजपा सरकार बनाने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि यह सरकार अपने सहयोगियों को स्वीकर पद या महत्वपूर्ण मंत्रालय देने की बजाय उन्हें आर्थिक लाभ देकर संतुष्ट कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि एक राज्य को लाभ देने के लिए दूसरे राज्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, 400 जिलों में खरीफ फसलों का क्रॉप सर्वे और तिलहनों के लिए एक कार्यनीति का निर्माण जैसे निर्णयों से कृषि क्षेत्र तेजी से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

100 दिनों के काम के लिए कोई दिशा नहीं ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बजट में 100 दिनों के काम के लिए कोई दिशा नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, जो कि वोटों की संख्या में बांग्लादेश के बराबर है, उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। गरीबों के लिए कोई राहत नहीं ममता ने बजट में सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसे धातुओं पर करों में कमी का भी जिक्र किया और कहा कि इससे गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों की अनदेखी करने वाला बजट है, जो सिर्फ अमीरों के लिए लाभकारी है।

बंगाल के बकाया की याद दिलाई

ममता ने कहा कि केंद्र के पास बंगाल का एक लाख 75 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं लेकिन फिर भी बंगाल के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने बजट में रोजगार के लिए कोई व्यवस्था न होने पर भी नाराजगी जताई।

बनाने और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही, मत्स्य सहकारिता को झींगा की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबाई के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा से नई गति मिलेगी।

गौरव गोगोई ने बजट को बताया कुर्सी बचाने व उद्योगपति को धनी बनाने वाला

गुवाहाटी। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उप नेता गौरव गोगोई ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि यह बजट कुर्सी बचाने और पूंजीपतियों को अमीर बनाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री का यह बजट बेहद निराशाजनक है। गौरव गोगोई मंगलवार को एक वीडियो संदेश जारी कर बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बजट दो राजनीतिक दलों को संतुष्ट करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए बनाया गया है। इस बजट से आम लोगों तथा गरीबों को निराशा हाथ लगी है। बजट में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि भाजपा को चंदा देने वाले पूंजीपति वर्ग और अधिक अमीर हो सकें।

बजट में तमिलनाडु के साथ अनदेखी, नीति आयोग की बैठक का करेंगे बहिष्कार: एमके स्टालिन

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि केन्द्रीय बजट में राज्य के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। स्टालिन ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया, क्योंकि केंद्र ने केंद्रीय बजट में तमिलनाडु का बहिष्कार किया है। केंद्रीय बजट पर चेन्नई में प्रेसवार्ता करते हुए एमके स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 साल से मेट्रो रेल की फंडिंग नहीं की है और इसकी कोई अधिसूचना भी नहीं है। केवल कुछ ही राज्यों के लिए बजट घोषणाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ मांगने के बावजूद राज्य में दो सबसे बड़ी आपदाओं के लिए केवल 236 करोड़ रुपये रखे गए हैं। तमिलनाडु में रेलवे परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में तमिलनाडु के साथ अन्याय किया गया है। केंद्र सरकार के भेदभाव के खिलाफ तमिलनाडु के सांसद कल विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसलिए दिल्ली में होने जा रही बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया गया है। वहीं, राज्यसभा सदस्य पी. विल्सन ने इसे बदले के भाव वाला बजट बताया है। उन्होंने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सोमवार को संसद में अपने भाषण के दौरान, तमिलनाडु में लंबित परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। इस बात पर जोर दिया था कि तमिलनाडु और उसके लोगों को राजनीतिक कारणों से भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। आज का केंद्रीय बजट इसी भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बजट अत्यधिक निराशाजनक है क्योंकि यह भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों के जवाब में तमिलनाडु और उसके लोगों को लक्षित करता प्रतीत होता है। तमिलनाडु के लिए आज का बजट बदले का बजट है।

केन्द्रीय बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य, बिहार की जरूरतों पर विशेष ध्यान: नीतीश

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत बिहार के मानव संसाधन विकास एवं बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बजट में बिहार की सड़क सम्पर्क परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की संरचनाओं के लिये विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में बिहार के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिये विशेष सहायता की घोषणा की गयी है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को बाढ़ से बचाव के लिये भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। कोशी-मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं के लिये विशेष आर्थिक मदद देने की घोषणा की गयी है, जो स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री ने बिहार के लिये बजट में विशेष प्रावधान के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बजट में बिहार के लिये की गयी इन घोषणाओं से बिहार के विकास में सहयोग मिलेगा। साथ ही उम्मीद जताई कि भविष्य में भी अन्य आवश्यकताओं के लिये केन्द्र सरकार इसी तरह बिहार के विकास में सहयोग करेगी।

भगवान बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क,
रांची में निर्मित

BILLION IMPRESSIONS
का उद्घाटन कार्यक्रम

24 जुलाई, 2024 | अपराह्न 12-30 बजे | भगवान बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क, रांची

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार तथा
The Indian Hotels Company Ltd. (A TATA Enterprise) के बीच

ताज होटल के निर्माण हेतु
MoU हस्ताक्षर कार्यक्रम

24 जुलाई, 2024 | अपराह्न 01-30 बजे | जे.जे.एच. आवास विभाग, रांची

मुख्य अतिथि

श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

विशिष्ट अतिथि

श्री हफीजुल हसन
माननीय मंत्री, उपसचिव, आवास विभाग, विकास विभाग,
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कर्तव्य विभाग,
नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार

श्री टी. वी. नरेन्द्रन
जी.डी.ओ. रांची, रा.क.डी.ओ.

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार

PR.No.- 330503 (Urban Development and Housing) 24-25

स्वत्वाधिकारी यशवंत धोटे के लिए प्रकाशक, मुद्रक मधुकर सिंह, मां तपेश्वरी मीडिया एंड पब्लिकेशन प्रा0 लिमिटेड, सिंहमोड़ कल्याणपुर हटिया, अपोजिट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, द्वारा रांची से प्रकाशित कर, तपो प्रिंटर, गुटूआ मौजा, प्लॉट नं.-1124/1125, कटहल मोड़, थाना-नगड़ी, दयाल पेट्रोल पंप के बगल में, रांची (झारखंड) से मुद्रित, (न्याय क्षेत्र रांची) संपादक-सचिन कुमार सिंह, स्थानीय संपादक-उपेन्द्र नाथ पाण्डेय* (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार), फोन नं.-0651-2910972, ईमेल - navpradeshraanchi@gmail.com (RNI No. JHAHIN/2016/68458)